● वर्ष-4
● अंक-156
रायपुर, शनिवार
08 फरवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

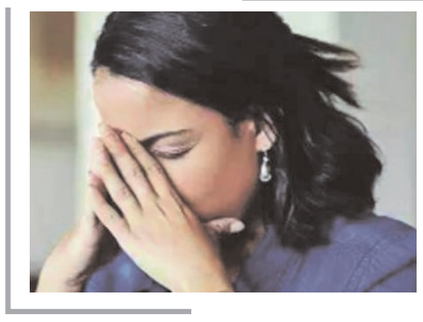

पेज-6» लगातार बनी रहती है थकान....

कौशल भारत के लिए 8800 करोड़ मंजूर

केंद्रीय कैबिनेट ने नए आयकर बिल पर भी लगाई मुहर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। इसमें कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ाया गया है। वहीं दक्षिण तटीय रेलवे जोन के विकास के लिए बड़ा फैसला लिया गया। वहीं सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने नए आयकर बिल को भी मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए 8,800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2026 तक कौशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी) को जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दी।

इससे देशभर में भविष्य के लिए कुशल, मांग पर आधारित, तकनीकी रूप से सक्षम और औद्योगिक रूप से प्रशिक्षित युवाओं को तैयार किया जा सकेगा। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), प्रधान मंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (पीएम-एनएपीएस) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना को जोड़ दिया गया। अब यह तीनों योजनाएं कौशल भारत कार्यक्रम का हिस्सा होंगी।

बजट में की थी घोषणा

नए आयकर बिल की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में घोषणा की थी। उन्होंने इस बिल को संसद के मौजूदा सत्र में पेश करने की बात कही थी। सूत्रों की मानें तो मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अगले हफ्ते इसे संसद में पेश किया जाएगा। संसद की मंजूरी के बाद यह छह दशक पुराने आयकर कानून की जगह लेगा। नए विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर कानून को समझने को आसान बनाना और कोई नया कर बोझ नहीं डालना है। इसकी खास बात यह होगी कि प्रावधान और स्पष्टीकरण या लंबे वाक्य नहीं होंगे।

सूत्रों ने कहा कि अगले हफ्ते संसद में पेश किए जाने के बाद बिल को संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के बजट में ही आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। सीबीडीटी ने समीक्षा की देखरेख करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था, जिससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी। आयकर अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियां बनाई गई हैं। चार श्रेणियों में जनता के इनपुट और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। ये श्रेणियां हैं भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में कमी और अनावश्यक/ अप्रचलित प्रावधान। आयकर विभाग को आयकर अधिनियम की समीक्षा पर हितधारकों से 6,500 सुझाव मिले हैं।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 के बाद तीन साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। इस फैसले से सरकार पर लगभग 50.91 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी, सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार होगा और खतरनाक सफाई करते समय शून्य मृत्यु दर का लक्ष्य हासिल होगा।मंत्रिमंडल ने दक्षिण रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन को संक्षिप्त रूप में बनाए रखने और इसका नाम बदलकर विशाखापत्तनम डिवीजन करने को मंजूरी दे दी। वाल्टेयर नाम एक औपनिवेशिक विरासत है जिसे बदलने की जरूरत है। वाल्टेयर डिवीजन का एक हिस्सा (जिसमें पलासा-विशाखापत्तनम-दुव्वाडा, कुनेरू - विजयनगरम, नौपाड़ा जंक्शन - परलाखेमुंडी, बोब्बिली जंक्शन - सलूर, सिम्हाचलम उत्तर-दुव्वाडा बाईपास, वडालापुडी-दुव्वाडा और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट-जग्गयापलेम स्टेशनों के बीच के सेक्शन शामिल हैं) को नए दक्षिण तटीय रेलवे के तहत वाल्टेयर डिवीजन के रूप में बनाए रखा जाएगा।

प्रदेश में अब ई-आफिस लगेगी

सभी विभागों में पूर्ण क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 तक

रायपुर। सरकार सुशासन को सशक्त बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, प्रभावी और त्वरित बनाने की दिशा में, 1 जनवरी 2025 को विभागीय सचिवों की बैठक में सभी विभागों और कार्यालयों में ई-ऑफिस को लागू करने के निर्देश दिए गए थे। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिकांश फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से ही निपटाई जा रही हैं और सभी विभागों में इसका पूर्ण क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 तक सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-ऑफिस के प्रशिक्षण की सुविधा देने की बात कही, ताकि सभी विभागों में इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है। पहले इसे सामान्य प्रशासन विभाग में शुरू किया गया था और अब इसे

सक्ती पहला ऐसा जिला है, जहां ई-ऑफिस पूरी तरह से लागू हो चुका है।

मंत्रालय के सभी विभागों में विस्तारित कर दिया गया है। अब तक 16 विभागाध्यक्ष कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है और जिला स्तर पर भी इसे लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सक्ती पहला ऐसा जिला है, जहां ई-ऑफिस पूरी तरह से लागू हो चुका है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि सभी विभागों में फाइलों की डिजिटल स्वीकृति सुनिश्चित की जाए, ताकि सरकारी कार्यों में अनावश्यक देरी समाप्त हो और प्रशासनिक निर्णयों को त्वरित रूप से लागू किया जा सके।राज्य सरकार डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर सशक्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस को प्रभावी रूप से लागू किया है, जिससे राज्य की सभी सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी, सुगम और त्वरित बनेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस को सुशासन के प्रभावी उपकरण के रूप में अपनाया गया है।

क्या होगा लाभ

- ई-ऑफिस प्रणाली से सरकारी कार्यों की गति, दक्षता और पारदर्शिता में अभूतपूर्व सुधार होगा
- सरकारी प्रक्रियाओं में स्वचालन आएगा, जिससे फाइलों की ट्रैकिंग आसान होगी, निर्णय लेने की गति तेज होगी
- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

प्रयागराज में तीनों अमृत स्नान (मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी) के बाद भी श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। पूरे देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से पवित्र त्रिवेणी में श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु प्रतिदिन लाखों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी के अंतिम अमृत स्नान पर्व के बाद भी करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान को पहुंच रहे हैं। इसमें 10 लाख कल्पवासियों के साथ-साथ देश-विदेश से आए श्रद्धालु एवं साधु-संत शामिल रहे।

दिल्ली दंगल में मोदी का मैजिक चला या केजरीवाल का

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा इस बार राजधानी में असर दिखा पाएगा या फिर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की सियासी रणनीति एक बार फिर सफल होगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कामयाब होने के बारे में शनिवार को मतगणना के बाद खुलासा होगा। दरअसल बीते दो विधानसभा चुनावों में भाजपा मोदी लहर के बावजूद दिल्ली में सरकार बनाने में असफल रही थी, जबकि केजरीवाल का मैजिक चलता रहा और आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। दूसरी ओर, कांग्रेस इन चुनावों में लगातार हाशिए पर ही रही है।

मोदी लहर में भी आप ने मारी बाजी

भाजपा के लिए यह चुनाव किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया और मोदी के नाम पर जीत दर्ज की, लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव का समीकरण हमेशा अलग रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस बार भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है, तो यह संकेत होगा कि मोदी की लोकप्रियता का असर राज्य स्तरीय चुनावों में सीमित हो सकता है। इसके विपरीत यदि भाजपा इस बार मजबूत प्रदर्शन करती है, तो यह संकेत होगा कि केंद्र सरकार की नीतियां और मोदी का करिश्मा अब दिल्ली की जनता को भी प्रभावित कर रहा है। दरअसल भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरूआत मोदी ने की थी और उन्होंने पांच सभा करके अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था।

इस बार दिल्ली को किस पर भरोसा?

अरविंद केजरीवाल ने पिछले दो चुनावों में भाजपा और कांग्रेस दोनों को शिकस्त दी थी और आप को दिल्ली में अभूतपूर्व सफलता मिली थी। उनके शासनकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त सुविधाओं पर जोर दिया गया, जिसने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाए रखा। हालांकि, इस बार भाजपा ने आक्रामक प्रचार अभियान चलाया और केजरीवाल सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। खासकर आप सरकार में हुए भ्रष्टाचार और विभिन्न मामलों में सरकार की नामाकी और अनेक वादे पूरे नहीं करने के मुद्दों को उठाते हुए भाजपा ने मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया।

प्रमुख समाचार

बांग्लादेशियों को ट्रंप स्टाइल में बाहर भेजने प्रदर्शन

नईदिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) ने केंद्र से आग्रह किया कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से प्रेरणा ले और इसी तरह अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या प्रवासियों को देश से निर्वासित करे। जम्मू में पार्टी की जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में एक प्रदर्शन में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने केंद्र से इसी तरह की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने पर विशेष जोर दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना, सीमा हैदर को वापस भेजो और अवैध रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों को निर्वासित करो जैसे नारे लिखी तख्तियां ले रखी थीं। भारत सरकार को डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन से सीख लेनी चाहिए और पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और पूर्व बांग्लादेशी राष्ट्रपति शेख हसीना सहित सभी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या अप्रवासियों को तुरंत निर्वासित करना चाहिए।

अमेरिका से और निकाले जाएंगे 487 अवैध भारतीय

नईदिल्ली। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 487 कथित भारतीय नागरिकों के बारे में सूचित किया है जिन्हें निष्कासन आदेश जारी किए गए हैं। मिस्री के अनुसार, इन व्यक्तियों को कथित तौर पर अमेरिका से संभावित निर्वासन का सामना करना पड़ रहा है। विदेश सचिव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी और आश्वासन दिया कि भारत सरकार अवैध अप्रवासी पाए गए भारतीयों की सुरक्षित वापसी की सुविधा के लिए ट्रम्प प्रशासन के संपर्क में है। मिस्री ने कहा कि भारत सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और इन व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ काम कर रही है। अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों के निर्वासन पर मिस्री ने कहा कि ईएएम द्वारा प्रतिबंधों के उपयोग से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया का विवरण, जो आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन सहित अमेरिकी अधिकारियों द्वारा हमें सूचित किया गया है। विदेश मंत्री ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि ये लंबे समय से चलन में हैं।

शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही इस्लामी समूह हुए एक्टिव

नईदिल्ली। ढाका विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के प्रोफेसर नजमुल अहसन कलीमुल्लाह ने स्वीकार किया कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में इस्लामी समूहों को अधिक स्वतंत्रता मिली है। कलीमुल्लाह ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में कई प्रतिबंधित इस्लामी संगठन सक्रिय हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। बिल्कुल। आप जानते हैं, इस्लामवादी, वे सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी जगह बनाने में सफल रहे हैं। वहीं बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। हिफाजत-ए-इस्लाम आंदोलन और मजबूत हो गया है। पीयर ऑफ चार्मोनी जैसी शख्सियतों को प्रमुखता मिली है। यहां तक ??कि हिज़्ब-उत-तहरीर भी एक गैरकानूनी संगठन है, लेकिन वे दिखाई दे रहे हैं। वे पर्चे, पोस्टर लेकर आ रहे हैं और अलग-अलग जगहों पर अपने झंडे लहरा रहे हैं, सड़कों पर मार्च कर रहे हैं, यहां तक ??कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला रहे हैं। इसलिए आधिकारिक तौर पर यह संगठन अब तक एक कानूनी इकाई नहीं है और उनका मीडिया समन्वयक सलाखों के पीछे है। इसलिए, आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध अभी भी है।

शरणार्थियों को जमीन देने के लिए कानून लाएगी सरकार

लखनऊ। प्रदेश सरकार विभाजन के समय पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए जमीन पर पूरा हक देने के लिए नया कानून लाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर विचार चल रहा है। सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के समाप्त होने के बाद मौजूदा नियमों के तहत उन्हें यह हक दे पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए नया कानून लाने की योजना बनाई गई है। 1947 में भारत-पाक विभाजन के समय पाकिस्तान से आए करीब 10 हजार परिवारों को लखीमपुर खीरी, रामपुर, बिजनौर और पीलीभीत में बसाया गया था। इन्हें सरकार की ओर से जमीन भी दी गई थी। इनमें से अधिकतर हिंदू और सिख शरणार्थी थे। लेकिन, इनमें से तमाम परिवारों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार नहीं मिला। यानी, इन परिवारों के वारिस अपनी जमीन पर बैंक से फसली ऋण के अलावा कोई और ऋण नहीं ले सकते। उन्हें जमीन बेचने का भी अधिकार नहीं है। ये शरणार्थी परिवार लंबे समय से संक्रमणीय भूमिधर अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इसलिए इनके दावों के परीक्षण के लिए शासन ने कुछ समय पहले मुरादाबाद के कमिश्नर, पीलीभीत के डीएम, लखीमपुर खीरी के एडीएम

अप्रवासियों से दुर्व्यवहार पर अमेरिकीयों से की जाएगी बात

नई दिल्ली। अमेरिका से भारत भेजे गए अप्रवासियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि अप्रवासियों से दुर्व्यवहार का मुद्दा हमारे सामने आया है। इस मुद्दे को लेकर हम अमेरिकी अधिकारियों से बात करेंगे। हम यह तय करेंगे कि निर्वासितों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी मामला हमारे सामने आएगा तो हम उसे अमेरिका के सामने उठाएंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने हमें आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के बारे में सूचित किया है। इस पर विदेश मंत्री ने मानक संचालन प्रक्रिया का विवरण दिया है। अवैध आव्रजन को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ पूरे सिस्टम में कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन के बाद कोई विरोध प्रदर्शन हुआ था। हमारे पास किसी विरोध प्रदर्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। विदेश सचिव ने कहा कि निर्वासन की प्रक्रिया नई नहीं है। इस बारे में विदेश मंत्री ने भी कल संसद में बताया था।

संसद डायरी

यूरोप में फेमस है हरियाणा की व्हिस्की, देश में यूरिया की किल्लत नहीं

संसद का बजट सत्र चल रहा है। आज दोनों ही सदनों में कामकाज देखने को मिली। हालांकि, विपक्षी सांसद लगातार अमेरिका से निर्वासित भारतीयों का मुद्दा उठाते रहे। दोनों ही सदनों में बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने बजट को लेकर अपना पक्ष भी रखा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम वाले एचपीवी (ह्यूनम पोपिलोमा वायरस) टीके को सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने को लेकर मंथन कर रही है। वहीं, भाकपा सदस्य ने जीसीसी देशों में रहने वाले भारतीयों की परेशानियों का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा कि भारत यूरोपीय संघ (ईयू) के नए व्यापार नियमों से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए उसके साथ बातचीत कर रहा है।

लोकसभा की कार्यवाही

कांग्रेस ने सरकार पर केंद्रीय बजट को तैयार करने की प्रक्रिया में राज्यों को शामिल नहीं करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि इस बजट में किसानों की अनदेखी की गई है। लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्य धरमवीर गांधी ने कहा कि हमारा देश राज्यों का संघ है, ऐसे में राज्यों से परामर्श कर बजट तैयार किया जाना चाहिए।

समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय प्रवासियों से जुड़ा विषय शुक्रवार को लोकसभा में उठाया और कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र कहते थे, फिर भारत के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हुआ। उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए आरोप लगाया कि भारतीय नागरिकों का अपमान हुआ और भारत

सरकार संवेदनाहीन बनी रही।

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि देश में यूरिया खाद की कोई किल्लत नहीं है और कुछ लोग मुनाफाखोरी के लिए इसके दामों को प्रभावित कर परेशानी पैदा कर रहे हैं। नड्डा ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि जन प्रतिनिधियों को और राज्य सरकार को इस तरह के तत्वों पर कार्रवाई करने में मदद करनी चाहिए।तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्रीय बजट को 'बांग्ला विरोधी बजट' करार दिया और आरोप लगाया कि इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को ''सांठगांठ वाले पूंजीवाद के रावण'' को सौंप दिया है तथा ''सीता माता की तरह'' देश के आम आदमी को गुमराह किया है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 'रिवर्स रॉबिनहुड' की महारथी है जो गरीबों से लेकर अमीरों को देती है। बनर्जी ने कहा कि सरकार 'अधूरे संघवाद' पर अमल कर रही है क्योंकि बिहार को देती है और पश्चिम बंगाल की उपेक्षा करती है।

राज्यसभा में जनता दल यू के संजय झा ने बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे का नाम मध्य काल के प्रसिद्ध मैथिल कवि विद्यापति पर रखे जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि विद्यापति ने भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मिथिला क्षेत्र के वासियों के दिलों में उनका अमिट स्थान है।राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य ने शुक्रवार को उच्च सदन में आय की बढ़ती असमानता का मुद्दा उठाते हुए इसे अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा करार दिया तथा इसे दूर करने के लिए केंद्र से तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मनोज झा ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि मध्यम और निम्न आय वर्ग की आय में गिरावट आई है, जबकि अमीरों की आय बढ़ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) मंच को किसानों के लिए 'वरदान' करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि अब तक 1.78 करोड़ किसान इससे पंजीकृत हो चुके हैं, 4,362 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) जुड़ चुके हैं और 239.6 करोड़ रुपये मूल्य की उपज का व्यापार हुआ है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए चौहान ने यह भी कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक लगभग 1,410 मंडियों को ई-नाम मंच से जोड़ा गया है।

पीयूष गोयल विदेश में उस समय भौचक रह गये जब स्विटजरलैंड के एक मंत्री ने उनके पास आकर, हरियाणा के गांव में बनी 'सिंगल माल्ट व्हिस्की' की जमकर प्रशंसा की और कहा कि यह यूरोप में काफी पसंद की जाती है, जबकि गोयल ने इसका नाम भी नहीं सुना था। उन्होंने निर्दलीय सदस्य कार्तिकेय शर्मा के एक पूरक सवाल के जवाब में कहा कि तीन महीना पहले वह एक बैठक के लिए ज्यूरिख (स्विटजरलैंड) में थे। गोयल ने कहा, ''मैं व्हिस्की नहीं पीता और मैं यह सुनकर चकित रह गया... मुझे नहीं पता था कि यह व्हिस्की यूरोप के बाजारों में प्रीमियम व्हिस्की के रूप में बिकती है।

अबूझमाड़ में आईटीबीपी का नया कंपनी ऑपरेटिव बेस

■ नक्सलियों की राजधानी कहलाने वाले कुतुल में सीओबी

रायपुर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में स्थित कुतुल में एक नया कंपनी ऑपरेटिव बेस (सीओबी) स्थापित किया है। कुतुल को नक्सलियों की राजधानी के रूप में जाना जाता है।

नए सीओबी की स्थापना से अबूझमाड़ में नक्सलियों की गतिविधियों में कमी आएगी और नियंत्रण होगा। अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है और राज्य के नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करने वाले सबसे दूरस्थ (रिमोट) और सबसे कम आवाजाही वाले क्षेत्रों में से एक है।

आईटीबीपी की 41वीं बटालियन ने बुधवार को नया सीओबी खोला। आईटीबीपी के सामरिक क्षेत्र मुख्यालय भुवनेश्वर (ओडिशा) और कोंडागांव (छत्तीसगढ़) के तहत बटालियन राज्य के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूझमाड़ में नक्सली गतिविधियों को कम करने और नियंत्रित करने के लिए नए

सीओबी खोलने का काम जारी रखे हुए है।

आईटीबीपी के अधिकारियों ने कहा कि नए सीओबी के खुलने से छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के मिशन कगार-2026 नक्सल उन्मूलन को गति मिलेगी और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

कुतुल नारायणपुर जिले के कोडेलियार से लगभग 5 किमी आगे है। अबूझमाड़ क्षेत्र में यह नक्सलियों की राजधानी जैसा है। यह मुख्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस कुतुल पोस्ट को खोलने पर आईटीबीपी ने कहा कि इससे वहां रहने वाली आबादी के मन में डर कम होगा और उनके दिलों में सुरक्षा की भावना पैदा होगी। आईटीबीपी ने कहा कि इससे नक्सलियों के इरादों पर काफी हद तक अंकुश लगेगा और क्षेत्र के लोगों को देश की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

देर रात घर में घुसकर नक्सलियों ने की सरपंच प्रत्याशी की हत्या

दंतेवाड़ा। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बीच माओवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए एक सरपंच प्रत्याशी की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने देर रात इस घटना को अंजाम दिया है। मामला दंतेवाड़ा जिले के धुर नक्सल प्रभावित अरनपुर पंचायत का है। जहां जोगा बारसा नाम के सरपंच प्रत्याशी की नक्सलियों ने गुरुवार रात को घर में घुसकर परिजनों के सामने हत्या कर दी। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक अरनपुर पंचायत से इस बार जोगा बारसा सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। गुरुवार की रात 7 से 8 की संख्या में नक्सली जोगा बारसा के सरपंच पारा में मौजूद घर में आ धमके। नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से वारकर घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। इसके बाद धारदार हथियार से वार कर जोगा की निर्ममता पूवर्क हत्या कर दी। परिजन बीच-बचाव करते हुए जोगा बरसा को छोड़ने की विनती करते रहे लेकिन नक्सलियों ने एक भी नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि नक्सली अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर कपड़े बांधे हुए थे। एसपी गौरव राय ने बताया घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही आसपास के इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गयी है। अरनपुर के ग्रामीणों ने बताया कि जोगा बारसा की पत्नी अरनपुर की सरपंच रह चुकी हैं। इस बार पुरुष सीट होने के कारण जोगा खुद सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। जोगा पहले से ही नक्सलियों के टारगेट में रहा है। इससे पहले भी उसे नक्सली धमकी दे चुके हैं। लेकिन गुरुवार रात नक्सलियों ने जोगा को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद अरनपुर और उसके आसपास के पंचायतों में दहशत का माहौल बना हुआ है।

भाजपा के 1 साल के कार्यकाल में परेशान हो चुकी जनता: भूपेश बघेल

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूर्वी सीएम भूपेश बघेल बीती रात बलौदा बाजार पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे प्रदेश में दौरा कर रहा हूं। लोग भाजपा के एक वर्ष के कार्यकाल को देख कर परेशान हो चुके हैं और पुन: परिवर्तन की लहर और कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। पूर्व सीएम ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं के हितों की चिंता करने वाली हिमायती नहीं, वरन शोषण करने वाली है।

उन्होंने कहा कि किसानों को धान की खरीद राशि भुगतान की बात कही थी, पूरा नहीं किया। गरीबों के स्वास्थ्य योजना को लेकर हमने जो योजना लागू किया, वह बंद कर दिया गया है। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए आत्मानंद स्कूल खोला, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि नाम बदलने की बात कह रहे हैं। वहीं शिक्षकों को बराबर वेतन नहीं मिल रहा है। युवाओं को नौकरी से निकाल दिये।

पूर्व सीएम ने आगे कहा कि भाजपा के शासन काल में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इनके प्रशासनिक अधिकारी नियंत्रण में नहीं हैं। बलौदाबाजार-भाटापारा का कलेक्टर एसपी कार्यालय जल गया और ये सम्हाल नहीं पाए। कलेक्टर एसपी कार्यालय छोड़कर भाग गये। निर्दोष लोगों को पकड़ जेल भेजा गया, जबकि वास्तविक अपराधी बाहर घुम रहे हैं। एक समाज विशेष को पकड़कर जेल में ठुंसा गया।

उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षकों को नौकरी से निकाला जा रहा है। शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। कांग्रेस की जितनी भी योजना थी, उसे भाजपा ने बंद करवा दिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं परेशान हैं।

उन्होंने आगे कहा कि झुठ फरेब से यह सत्ता में काबिज है, पर अब जनता समझ गयी है और अब प्रदेश में बदलाव की स्थिति है। पूर्व सीएम बघेल ने इन मुद्दों पर भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए लोगों से कांग्रेस को वोट देकर जिताने की अपील की है।वहीं अमरिका से पंजाब लाए गए भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार को लेकर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को संज्ञान लेकर काम करना चाहिए।

जनसभा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि शैलेष नितिन त्रिवेदी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कालनेमि रूपी है, जो वक्त के साथ रंग बदल देते हैं। मीठी बातें कर जनता को गुमराह करते हैं। इनसे बचकर रहना और कांग्रेस प्रत्याशियों का वोट देकर हाथ मजबूत करना।

अधिवक्ता बेला ने भी तोड़का मुठभेड़ को बताया फर्जी

बीजापुर। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो समता ने 5 फरवरी को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एक फरवरी को बीजापुर जिले के तोड़का में हुए मुठभेड़ को फर्जी बताया, जिसके बाद आज शुक्रवार को अधिवक्ता बेला भाटिया के द्वारा मीडिया को जारी प्रेस नोट एवं गंगालूर थाना के सामने ग्रामीणों की ली गई एक फोटो के माध्यम से बताया गया कि मैंने कोरचोली-तोडका में 1 फरवरी 25 को हुई तथाकथित मुठभेड़ की जांच की है, और उसे फर्जी पाया है।

जांच उपरांत मृतक और घायलों के परिजनों को पुलिस शिकायत लिखवाने में मदद कर 5 फरवरी 25 को गंगालूर थाना ले कर गए थे । लेकिन गंगालूर थानेदार ने शिकायत यह कह कर नहीं ली कि पुलिस के खिलाफ की जा रही कोई शिकायत नहीं ली जाएगी। उसके बाद हम सब थाना के नजदीक धरना पर बैठ गए थे। वहीं आयुर्वेदिक हस्पताल के बगल के शेड में हम सब ने रात बिताई। इस बीच शीर्ष पुलिस अधिकारियों आईजी और डीआईजी बस्तर को इसकी जानकारी दी और उन्हें न्याय संगत कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। हमारा कहना था कि अगर लोगों को एक शिकायत दर्ज करने के बुनियादी अधिकार को भी नहीं माना जाता है, तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा । इस बात पर फिर हमारी बात सुनी गई । अंततः 19 घंटों के बाद 6 फरवरी को डीएसपी गंगालूर द्वारा शिकायत ली गई।

बेला भाटिया द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि शिकायत में मृतक और घायल ग्रामीणों के परिजनों का कहना है कि 1 फरवरी 25 की सुबह कोरचोली-तोडका के कुल 7 ग्रामीणों एवं कुटरू के एक ग्रामीण को पुलिस द्वारा गोली और चाकू से मार कर हत्या की गई है, उस दिन कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी। प्रेस नोट में यह भी कहा गया कि उस दिन सुबह बड़ी संख्या में फोर्स ने गांवों को घेरा था और लोगों को भगाकर तोडका के नजदीक वाले पहाड़ तक खदेड़ा गया, वहां पूर्व से फोर्स तैनात थी। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, इस फाईरिंग में 8 ग्रामीण मारे गए और कुछ लोग घायल हुए जिनमें घायलों में दो ग्रामीण का अस्पताल में उपचार जारी है। मृतकों में केवल एक कमलेश नीलकंठ जो कुटरू गांव का निवासी था, वह नक्सली दलम का सदस्य था, लेकिन उस वह दिन बिना हथियार या वर्दी के अपने रिश्तेदारों से मिलने आया हुआ था। बेला भाटिया द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि हमारी मांग है कि इस शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो।

दल्लीराजहरा नगर पालिका में पलायन बड़ी चुनौती

■ अध्यक्ष के लिए भाजपा की लड़ाई, 24 साल से कांग्रेस का कब्जा

बालोद। बालोद जिले के सबसे बड़े नगर पालिका दल्ली राजहरा में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। इस नगर पालिका में बीजेपी 24 साल का सूखा खत्म करने के इरादे से उतरी है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि इस बार भी वहां पर कांग्रेस शहर की सरकार चलाएगी, आपको बता दें भाजपा ने इस बार अध्यक्ष पद के लिए तोरण साहू को मैदान में उतारा है तो वहीं कांग्रेस ने रवि जायसवाल को, शहर की लड़ाई दिलचस्प हो चली है बीजेपी को सभी नेताओं का साथ मिल रहा है तो वहीं कांग्रेस की मॉनिटरिंग पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया कर रही है।

दल्ली राजहरा नगर पालिका की बात करें को शहर बचाने का मुद्दा यहां पर हावी रहा है। स्थानीय नेता स्वाधीन जैन का कहना है कि इस शहर से करोड़ों की रॉयल्टी जिले में मिलती है। लेकिन इस शहर को कुछ भी नहीं मिल पाता है। पहले यहां की आबादी लाखों में थी लेकिन अब सिमटने लगी है। इससे लोग पलायन कर रहे हैं। आपको बता दें कि शहर में 100 बिस्तर अस्पताल की मांग लंबे समय से की जा रही है।वहीं जिले का नाम बदलने की मांग भी इसी शहर से उठी है जिसमें यह मांग किया जा रहा है कि जिले का नाम बदलकर बालोद - दल्ली किया जाए। वहीं बीजेपी प्रत्याशी तोरण साहू ने कहा कि लंबे समय से यहां कांग्रेस की सरकार है और इस सरकार ने शहर में राज करते हुए शहर को उजाड़ कर रख दिया है।

भाजपा प्रत्याशी तोरण साहू ने कहा हम यहां सुशासन लाने के उद्देश्य से मैदान में है। यहां पर शिक्षा स्वास्थ के लिए काम करेंगे। दो नए प्लांट की स्थापना यहां होने जा रही है। वहां स्थानीय लोगों को भरपूर रोजगार मिल सके इसलिए हम काम करेंगे। शहर से पलायन ना हो सभी सुविधाएं यहां मिल जाए इस पर पूरा जोर रहेगा।

इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रवि जायसवाल ने कहा कि लंबे समय से हमारी यहां नगर सरकार है। हमने इस शहर के लिए काफी कुछ किया है। जो कुछ नहीं कर पाए उसे करने के लिए हम मैदान में उतरे हुए हैं।

कांग्रेस प्रत्याशी रवि जायसवाल ने कहा यहां पर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए हम काम करेंगे नगर पालिका का उपाध्यक्ष भी रहा हूं। पार्टी ने इस बार अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है तो बिल्कुल बायपास से लेकर पट्टा जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहेंगे।

आपको बता दें कि दल्ली राजहरा में पिछले 24 साल से नगर सरकार कांग्रेस की है।पिछली बार कांग्रेस का शासन राज्य में था।इसके बाद भी ऐसी कई मांगें थी जो पूरी नहीं हुई।वहीं अब जब प्रदेश में सरकार बदली है तो नगर सरकार बदलने के लिए भी पुरजोर कोशिश की जा रही है।जहां एक ओर बीजेपी ने नगर पालिका जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई है।वहीं कांग्रेस ने अपनी गद्दी बचाने के लिए समीकरण तय किया है।

अंबिकापुर में वार्ड क्रमांक 12 और 14 की जनता का मूड

इशारों में बताया किसे चुनेंगे अपना नेता

सरगुजा। अंबिकापुर नगर निगम चुनाव में कहां पर कौन आगे है और कौन पीछे। पार्षद ने काम किया है या नहीं। जनता के मन में क्या है। क्या वो अपने पार्षद को दोहराएगी या फिर बदलेगी ऐसे कई सवाल हैं जो सभी के मन में है। मीडिया ने इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की है। अंबिकापुर नगर निगम में वार्डों के बीच जाकर वहां रह रही जनता से मीडिया ने उनकी समस्याओं और समाधान के बारे में जाना। इस बार बारी वार्ड क्रमांक 12 और 14 की थी। जहां की जनता ने बताया वो इस बार किसे चुनने जा रही है।

बातचीत में लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी हैं, कोई कहता है विकास हुआ ही नही। कोई कहता है काम तो हुए लेकिन सब कुछ कर पाना संभव नही होता है। किसी का कहना है कि नाली बनी लेकिन ढक्कन नहीं लगाए गए। तो किसी के क्षेत्र में नाली नहीं बनी। बीजेपी की विचारधारा का व्यक्ति बीजेपी को ही वोट करना चाहता है और कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति कांग्रेस को। स्थानीयता कुछ लोगों के लिये मायने नहीं रखती, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रत्याशी के चेहरे पर मतदान करेंगे।

वार्ड क्रमांक 12 नमनाकला से कांग्रेस के प्रमोद चौधरी और बीजेपी के मनोज गुप्ता के बीच सीधा मुकाबला है। प्रमोद चौधरी पिछली बार भी पार्षद रहे लेकिन सामने के वार्ड नंबर 14 से वो पार्षद थे। आरक्षण के कारण उन्हें 12 से चुनाव लड़ना पड़ा। जाहिर है कि इस वार्ड की समस्याओं के लिए वो जिम्मेदार नही हैं।लेकिन उनके पुराने वार्ड नंबर 14 में हुए काम से लोग काफी हद तक संतुष्ट नजर आएं। हालांकि शहरी मतदाता होशियार हैं वो अपने मन की बात खुलकर नही करता है, वोट किसे देंगे ये स्पष्ट किसी ने नही कहा। बातचीत के इशारों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वार्ड नम्बर 12 की जनता का मूड क्या है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

विधायक विक्रम के खिलाफ कवासी ने की थाने में शिकायत

बीजापुर। निकाय चुनाव से पहले बीजापुर की राजनीति में उबाल आ गया है। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के खिलाफ योगेश कवासी धक्का मुक्की का आरोप लगाकर कोतवाली में लिखित शिकायत की है। दरअसल, गुरुवार को विधायक विक्रम मंडावी व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता के दौरान प्रधानमंत्री आवास बनाने के फार्म भरते शांतिनगर में कुछ लोगों को पकड़ा था। इसके बाद जब्त फार्म को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी को सौप कर आचार संहिता उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग सहित अन्य भाजपा नेता कोतवाली पहुंचे। यहां शांतिनगर निवासी योगेश कवासी के नाम कोतवाली में लिखित शिकायत की गई। आवेदन में धक्का-मुक्की का आरोप लगाकर अंदरूनी चोट आने का जिक्र है।

45.50 लाख रूपये की 750 पेटी शराब जब्त

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में 45.50 लाख रुपए कीमत के 750 पेटी शराब जब्त किया गया है। यह कार्रवाई बेमेतरा आबकारी विभाग ने किया है। इस मामले में दो आरोपी को पकड़ा गया है, जिनसे विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे है। इस शराब को एमपी से लाया जा रहा था। अधिकारियों को शक है कि इस माह होने वाले निकाय व पंचायत चुनाव में इन शराब को खपाया जाना था। खास बात यह है कि बीते दो दिन के भीतर बेमेतरा जिले में ये तीसरी कार्रवाई है। पुलिस व आबकारी विभाग ने अब करीब 75 लाख रुपए से अधिक शराब जब्त किया है। ये सभी शराब एमपी से निर्मित है। वर्तमान में 45.50लाख रुपए कीमत के 750 पेटी शराब के संबंध में बताया जा रहा है कि इसे एमपी से चिल्फी (कबीरधाम) होते हुए लाया जा रहा था। इस शराब को कंटेनर ट्रक में भरकर रखा गया था। पुलिस व आबकारी विभाग से बचने के लिए तस्करों ने कंटेनर के अंदर प्लास्टिक के थर्माकोल को रखा गया था। इस पूरे मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई जारी है।

हाथियों की आहट से दहशत में मरवाही के गांव

गौरेला पेंड्रा मरवाही। करीब 2 महीने के बाद एक बार फिर हाथियों ने मरवाही वन मंडल में दस्तक दी है। गांव वालों का कहना है कि दल से बिछड़े हुए 2 हाथी इलाके में पहुंचे हैं। मरवाही के सीमावर्ती इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। गांव के पास हाथियों की मौजूदगी के चलते दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम भी लगातार हाथियों के हर मूवममेंट पर नजर बनाए हुए है। गांव के लोग आग जलाकर रात को पहरा देने की तैयारी में जुटे हैं। वन विभाग की टीम ने गांव वालों को सतर्क करते हुए कहा कि वो हाथियों के पास नहीं जाएं। हाथियों से दूरी बनाकर रखें। वन विभाग के अफसरों ने हाथियों को गांव में घुसने से रोकने के लिए कर्मचारियों की टीम को काम पर लगाया है। गांव वालों का कहना है कि गुरुवार देर रात तक दोनों हाथी देवगवा, डोंगराटोला इलाके में घुसे। धान के लालच में हाथियों ने कई घरों की दीवार को भी तोड़ दिया। गांव वालों ने जब शोर मचाया तो हाथी वहां से भागे।

9 फरवरी को होगी छग पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जगदलपुर शहर के 10 परीक्षा केन्द्रों पर 9 फरवरी 2025 को दो पाली क्रमश: प्रात: 10 से 12 बजे तक और अपरान्ह 3 बजे से सांयकाल 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। उक्त प्री-एक्जाम शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धरमपुरा नम्बर-2 जगदलपुर, शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय जगदलपुर, झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज धरमपुरा नम्बर-3 जगदलपुर, जगतू माहरा शासकीय बहुउद्देश्यीय हायर सेकंडरी स्कूल जगदलपुर, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हायर सेकंडरी स्कूल जगदलपुर, सेजेस शासकीय गर्ल्स हायर सेकंडरी स्कूल जनसम्पर्क कार्यालय के पीछे गीदम रोड जगदलपुर, निर्मल हायर सेकंडरी स्कूल लालबाग जगदलपुर, बाल विहार हायर सेकंडरी स्कूल आंध्रा समाज भवन के पास जगदलपुर, हम अकादमी मेन रोड कालीपुर जगदलपुर एवं क्राईस्ट कॉलेज राजेन्द्र नगर वार्ड गीदम रोड जगदलपुर में होगी।

तेलंगाना में बंधक बनाए गए छत्तीसगढ़ के 150 मजदूर

रायगढ़। तेलंगाना के ईंट भट्ठे में छत्तीसगढ़ के झारा परिवार के 150 से ज्यादा मजदूरों को बंधक बनाया गया है। वहीं एक मजदूर की मौत के बाद भी ईट भट्टी का मालिक मजदूरों को नहीं छोड़ रहा। मृतक के शव को एंबुलेंस से रायगढ़ लाया गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मदद की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक, मृतक का नाम नवीन झारा है। रायगढ़ जिले से 150 से ज्यादा मजदूर लंबे समय से काम की तलाश में तेलंगाना गए थे। इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं है। वहां मजदूर को बंधक बनाकर ईंट भट्?ठे के मालिक काम करा रहे। उन्हें घर जाने नहीं दिया जा रहा। वहीं एक मजदूर की ईंट भट्?ठे में काम करने के दौरान मौत हो गई। इसके बाद भी मजदूरों को नहीं छोड़ा गया। आज मृतक का शव एंबुलेंस से रायगढ़ लाया गया।

रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने किया दंतेवाड़ा के विकास कार्यों का अवलोकन

दंतेवाड़ा। रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के अध्ययन यात्रा-2025 के अंतर्गत 18 वरिष्ठ अधिकारियों का दल दंतेवाड़ा पहुंचकर जिले में संचालित सामाजिक और आर्थिक उत्थान से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का अवलोकन किया। साथ ही जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

अधिकारियों ने सबसे पहले गीदम स्थित डेनेक्स फैक्ट्री का निरीक्षण किया। उन्हें बताया गया कि स्थानीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री की शुरुआत की थी। इस फैक्ट्री में निर्मित कपड़ों को डेनेक्स ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जाता है। जिले में चार फैक्ट्रियों की स्थापना की जा चुकी है, जिनका लक्ष्य लगभग 1,200 परिवारों को रोजगार देना है।

यहां अधिकारियों ने कामकाजी महिलाओं से चर्चा कर उनका उत्साहवर्धन किया।

इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने कारली स्थित नक्सल पीड़ित पुनर्वास केंद्र का अवलोकन किया। अधिकारियों को अवगत कराया गया कि लोन वर्रातू (घर वापसी) अभियान के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सली हिंसा से पीड़ित परिवारों को सुरक्षित आवास एवं रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से इन परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रतिनिधि मंडल ने एजुकेशन सिटी जावंगा का भी दौरा किया, जहां उन्होंने सक्षम-2 (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आवासीय विद्यालय) में छात्रों से बातचीत की और उनकी उपलब्धियों की सराहना की। अधिकारियों को बताया गया कि दृष्टिबाधित छात्रों की पढ़ाई के लिए एनी डिवाइस नामक स्मार्ट लर्निंग टूल उपलब्ध कराया गया है, जो ब्रेल लिपि सीखने और पढ़ने में सहायक है।

इसके अलावा, अधिकारियों ने अश्व संचालन (घुड़सवारी) प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन किया, जहां छात्रों को घुड़सवारी की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। इस दौरान छात्रों ने गीत-संगीत की प्रस्तुति भी दी, जिसे सभी ने सराहा।

दल ने नव गुरुकुल संस्था द्वारा छात्रों को दी जा रही नि:शुल्क सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कक्षाओं का भी अवलोकन किया। उन्हें बताया गया कि 18 महीने के इस पाठ्यक्रम के तहत छात्रों को पीईटी, पीएमटी, आईआईटी, जेईई जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। इसके अलावा, छात्रों को इंग्लिश कम्युनिकेशन और लीडरशिप से जुड़े विशेष सत्र भी कराए जा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने जिले में शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और नक्सल पीड़ितों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और इसे अन्य स्थानों के लिए प्रेरणादायक मॉडल बताया।

सर्चिंग पर निकले बीएसएफ के जवानों ने दुर्घटना में घायल बाईक सवार युवक की बचाई जान

कांकेर। जिले के घुर नक्सल प्रभावित इलाका परतापुर-कोयलीबेड़ा मार्ग पर ग्राम महला के पास एक बाईक सवार युवक दुर्गासाय दुग्गा दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। उक्त घटना के दौरान सर्चिंग पर निकले बीएसएफ 47 बटालियन महला कैंप के जवान दुर्घटना में घायल बाईक सवार युवक को प्राथमिक उपचार देकर, बीएसएफ की एम्बूलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल, पंखाजूर पहुंचाया गया, जहां युवक का उपचार जारी है। युवक के आधार कार्ड से उसकी पहचान दुर्गासाय दुग्गा, पिता रामसाय दुग्गा, उम्र 40 वर्ष, निवासी- डोटोमेटा, उदयपुर, कांकेर के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को लगभग शाम 8:30 बजे परतापुर - कोयलीबेड़ा मार्ग पार ग्राम महला की ओर जानेवाली सड़क के पास एक मोटर साईकिल रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर से टकराकर दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें एक ग्रामीण दुर्गासाय दुग्गा, पिता रामसाय दुग्गा, उम्र 40 वर्ष, निवासी- डोटोमेटा, उदयपुर, कांकेर गंभीर रूप से

घायल हो गया और सड़क पर दर्द से तड़प रहा था। उक्त घटना के समय 47 बटालियन बीएसएफ (महला कैंप) की पार्टी उसी इलाके के जंगल में सर्चिंग-गश्त पर थी। घायल व्यक्ति को तड़पता देखकर जवानों के द्वारा प्राथमिक उपचार देकर बीएसएफ की एम्बूलेंस से सिविल अस्पताल, पंखाजूर पहुंचाकर युवक की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की। विजेंद्र नाथ गंगोली कमांडेंट, 47 बटालियन बीएसएफ के आदेशानुसार, जवानों की त्वरित कार्रवाई से घायल व्यक्ति की जान बच गई।

संक्षिप्त समाचार

भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के खिलाफ हाईकोर्ट ने मंजूर की संशोधित याचिका

बिलासपुर। बिलासपुर से भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के खिलाफ हाईकोर्ट ने संशोधित याचिका मंजूर कर ली है। पूजा विधानी के ओबीसी प्रमाण पत्र पर आपत्ति की गई है। बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने कोर्ट में संशोधित याचिका दायर कर आपत्ति जाहिर की है। बता दें कि लिपिकीय त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता को पहले याचिका वापस लेनी पड़ी थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता को दुबारा याचिका दायर करने का लिबर्टी दिया था। अब रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार बनाकर दोबारा याचिका पेश की गई है। अब आगामी 10 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई तय की गई है। वहीं 11 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए मतदान की तिथि पहले से तय हैं।

विस अध्यक्ष रमन सिंह के प्रचार पर कांग्रेस को आपत्ति

रायपुर। कांग्रेस ने निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखाकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ। रमन सिंह के नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में प्रचार करने पर शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए प्रचार पर तत्काल रोक लगाते हुए रमन सिंह पर उचित कानून कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि विभाग की ओर से निर्वाचन आयुक्त को लिखे पत्र में कहा गया कि राज्य में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर 20 जनवरी से आचार संहिता लागू है। ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष डॉ। रमन सिंह का नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का प्रचार-प्रसार करना आपत्तिजनक है। कांग्रेस विधि विभाग ने पत्र में डॉ। रमन सिंह के विधान सभा के अध्यक्ष के संवैधानिक पद पर होने के बाजवूद भाजपा का प्रचार-प्रसार करना आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन बताते हुए विरोध दर्ज कराया है।

चोरी करने से नाकाम रहे शातिर चोर गार्ड ने लाठी लेकर गलियों में दौड़ाया

रायपुर। राजधानी रायपुर स्थित एक कॉलोनी में चोरी करने घुसे चोरों को गार्ड ने जमकर दौड़ाया। जैसे-तैसे चोर कॉलोनी से भाग निकले। गार्ड की बहादुरी और सूझबूझ से कोई बड़ी वारदात होते-होते बचा। पूरा मामला मोवा इलाके का है। जहां चार चोर मुंह में कपड़ा बांधकर एक सोसाइटी के भीतर घुस गए। उनका सामना कॉलोनी के बहादुर गॉर्ड से हो गया। गॉर्ड ने डंडा लेकर चोरों को कॉलोनी के भीतर गलियों में जमकर दौड़ाया है। जिसके बाद चोर अपनी जान बचाते हुए भाग निकले। इस पूरी वारदात का वीडियो भी सामने आया है। इसमें चोर जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। चोरी करने की नीयत से चोर एक घर के पीछे से कंसर्टिना तार काटकर घर के पोर्च से होते हुए मेन गेट तक पहुंच गए थे। चोर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे थे, जिसे देखते ही गार्ड ने डंडा लेकर दौड़ाया और चोरों को भगाने में कामयाब रहे। बता दें कि चोर जिसे रस्ते से घुसे थे, उसी रास्ते से भाग निकले। गार्ड ने बहादुरी दिखाते हुए चोरों का पीछा किया। सभी बदमाश बाउंड्री से कूदकर भाग निकले। कॉलोनी के लोगों ने गार्ड की बहादुरी की सराहना की। इसके साथ ही पुलिस से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

राजधानी में आधी रात हंगामा करने वाली रशियन नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आधी रात हंगामा मचाने वाली लड़की रशियन नहीं है। पुलिस की पूछताछ से पता चला कि युवती उज्बेकिस्तान की रहने वाली है। युवती 30 जनवरी को टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। इस दौरान वे रायपुर आई थी। दरअसल, युवती नशे में धुत होकर भारत सरकार की गाड़ी चला रही थी। इस दौरान उसने स्कूटी में सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी। कार से उतर कर नशे में धुत युवती हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी। इधर रायपुर समेत पूरे प्रदेश में चर्चा है कि राजधानी रायपुर में अब रशियन लड़कियां आ रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, वीआईपी रोड में बुधवार रात हंगामा करने वाली युवती रशियन नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान से रायपुर आई थी। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि वो भारत 30 जनवरी को टूरिस्ट वीजा पर आई थी। 15

महेंद्र ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- निष्क्रिय रहा है बीरेंद्र का कार्यकाल

रायपुर। जैसे-जैसे नगरीय निकाय चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही हैं। वैसे-वैसे प्रदेश की सियासत गरमा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के महापौर और पार्षद प्रत्याशी चुनाव में पूरी ताकत झोंक दिये हैं। ऐसे में रायपुर नगर निगम के माधवराव सप्रे वार्ड क्रमांक 69 के बीजेपी पार्षद प्रत्याशी महेंद्र औसर ने कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी बीरेंद्र देवांगन पर निशाना साधा है। उनके पांच साल के कार्यकाल पर सवाल उठाये हैं। उनके पांच साल के कार्यकाल को निष्क्रिय करार दिया। मीडिया से बातचीत में बीजेपी पार्षद प्रत्याशी महेंद्र औसर ने कहा कि 15 साल से वार्ड में निर्दलियों का कब्जा रहा है। इसके चलते वार्ड में लोगों को किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई। बिजली, सड़क, पेयजल, आवास आदि का अभाव रहा है। नल-जल का बुरा हाल है। भाजपा ने भरोसा जताकर मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है तो लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य करेंगे। ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है तो वार्ड में काम करने में उत्साह दोगुना हो जायेगा। केंद्र और राज्य में हमारी सरकार, हमारे विधायक हैं।

अब छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंपों पर भी होगी वाहनों की प्रदूषण जांच

परिवहन विभाग और पेट्रोलियम कंपनियों के बीच बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पम्पों पर वाहनों की प्रदूषण जांच के सेंटर (पीयूसी) स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पेट्रोलियम कम्पनियों ने अपनी सहमति दे दी है। पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित होने से वाहन चालकों को पीयूसी प्रमाण पत्र बनवाने में आसानी होगी और उन्हें अन्य केंद्रों की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, यह पहल वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मददगार और राज्य में पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 4 फरवरी 2025 को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में वाहनों के धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत 7 फरवरी 2025 को परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश और अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र (पीयूसी सेंटर) स्थापित करने पर सहमति जताई। यह निर्णय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बैठक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुख्य प्रबंधक उपेन्द्र गिरी, भारत पेट्रोलियम के चीफ मैनेजर श्री बी. देवकुमार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधक श्रेयस गुप्ता और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मुख्य प्रबंधक गौतम कुमार सहित परिवहन विभाग और पेट्रोलियम कंपनियों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम साय का 8 और 9 फरवरी को भव्य रोड शो

8 फरवरी को जगदलपुर और रायपुर में करेंगे भव्य रोड शो

9 फरवरी को धमतरी और दुर्ग जिले में होगा रोड शो

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व नगरीय निकाय चुनाव के प्रदेश संयोजक श्री भूपेंद्र सवन्नी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 8 और 9 फरवरी को जगदलपुर, रायपुर, दुर्ग और धमतरी जिले में नगरीय निकाय के प्रत्याशियों के समर्थन में भव्य रोड शो करेंगे।

श्री सवन्नी ने बताया कि 8 फरवरी को जगदलपुर जिले में दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के भव्य रोड शो का एयरपोर्ट से शुभारंभ होगा। जहां से वे शहीद पार्क कोतवाली चौक गोलबाजार होते हुए सीरासार, दंतेश्वरी मंदिर, गुरुनानक चौक, पनामा चौक, महारानी रोड होते हुए चांदनी चौक पहुंचेंगे, जहां रोड शो का समापन कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अपराह्न 3 बजे राजधानी रायपुर में रोड शो करेंगे, जो खमतराई से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न इलाकों के मुख्यमार्ग से गुजरेगी।

श्री भूपेंद्र सवन्नी ने बताया, इसके अगले दिन 9 फरवरी को दुर्ग और धमतरी जिले में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय भव्य रोड शो की अगुवाई करेंगे।

श्री सवन्नी ने बताया कि 9 फरवरी को दोपहर 12 बजे धमतरी जिले में रोड शो करेंगे। तत्पश्चात मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय दुर्ग जिले में भव्य रोड शो करेंगे। जिसका शुभारंभ नया बस स्टैण्ड दुर्ग से होगा। जहां से रोड शो तकिया पारा चौक, मान होटल चौक से होते हुए पंचमुखी मंदिर चौक, चंडी मंदिर चौक, गवली चौक, सिद्धार्थ नगर चौक, उतई टेम्पो स्टैण्ड, लक्ष्मीबाई चौक होते हुए महाराजा चौक पहुंचेगी, जहां रोड शो का भव्य समापन होगा।

निकाय चुनाव को लेकर जनता में भारी उत्साह विकास के लिए भाजपा को देगी आशीर्वाद : साव

भाजपा अपने काम के दम पर निकायों में दर्ज करेगी जीत

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने रायपुर निवास में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। युवा और महिलाओं का उत्साह बता रहा है कि शहरों की जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रसन्न है। भाजपा अपने काम के दम पर निकायों में जीत दर्ज करेगी। भूपेश बघेल ने अपने पांच साल के कार्यकाल में किस शहर में क्या विकास कार्य किए, ये लोगों को बताना चाहिए। उनके पास बताने के लिए कुछ उपलब्धि नहीं है।

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि, भाजपा सरकार ने धान खरीदी की बेहतर व्यवस्था की है।हमने किसानों को धान के समर्थन मूल्य से अधिक राशि दी है। इनके समय किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नगरों के चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। वे रायपुर में कोई बड़ी उपलब्धि बता दें। भूपेश बघेल शहरों को दुर्दशा करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इस बार जनता विकास के लिए भाजपा को चुनेगी। कांग्रेस को उसके कुशासन का शानदार तोहफा देने के लिए तैयार है।कांग्रेस को शराब, चावल और कोयला घोटाले का श्रेय लेना चाहिए। साव ने तंज कसते हुए कहा कि, कांग्रेस में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए होड़ मची है। ये लोग पांच साल भी लड़ाई करते हुए गुजार दिए। इनकी लड़ाई के चलते छत्तीसगढ़ की जनता ने तकलीफ झेला है। अब विपक्ष में आ गए हैं, तब भी आपस में झगड़ रहे हैं। प्रदेश के मतदाता समझदार हैं, वोट डालने से पहले इस पर भी विचार करेंगे। आपस में लडऩे और झगडऩे वालों को शहरी सत्ता नहीं सौंपेंगे।

जो प्रशिक्षण को गंभीरता से पूरा करता है, वही आगे चलकर बनता है एक सफल प्रशासक : प्रमुख सचिव

रायपुर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग में नवनियुक्त सहायक संचालक और जनपद सीईओ ने विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा से मंत्रालय महानदी भवन स्थित उनके कक्ष में सौजन्य मुलाकात की। गौरतलब है कि नवनियुक्त अधिकारियों का छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित होने के बाद विभाग में पदस्थापना दी गई है। इन अधिकारियों का राजधानी रायपुर के प्रशासन अकादमी निमोरा में आगामी 10 फरवरी से आधारभूत प्रशिक्षण होगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभाग में सहायक संचालक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के 10-10 रिक्त पदों के लिए भर्ती की गई है।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने इस दौरान नवनियुक्त अधिकारियों का परिचय जाना और अपने सेवाकाल के अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि नियुक्ति के पश्चात किस प्रकार प्रारंभिक वर्षों में कार्यो को सीखने के दौरान अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपने प्रशिक्षण सत्र को पूरी गंभीरता के साथ पूर्ण करता है, वही आगे चलकर एक सफल प्रशासक बनता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने आपको यह सुनहरा मौका प्रदान किया है। इसके माध्यम से आप सरकार की योजनाओं को वंचित वर्ग तक पहुंचाकर राष्ट्रनिर्माण एवं देशसेवा की अपनी महत्ती भूमिका निभा सकते हैं।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि निर्धारित शेडयूल के अनुसार सभी नवनियुक्त अधिकारियों को 10 फरवरी से प्रशासन अकादमी, निमोरा में आधारभूत प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों से प्रशिक्षण के इस सत्र का पूरा लाभ लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी के लिए यह प्रशिक्षण सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान उन्हें प्रशासनिक कार्यप्रणाली की सभी बारीकियों को विषय विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से समझाया जाता है। अत: इसका पूरा लाभ लेने हेतु उनके द्वारा निर्देशित किया गया। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को नवा रायपुर में निर्माणाधीन ट्रॉयबल म्यूजियम एवं लायब्रेरी का भ्रमण करने को भी कहा। इस मौके पर उपसचिव श्री बी.के.राजपूत, अपर संचालक श्री आर.एस.भोई, उपायुक्त श्री एल.आर.कुर्रे उपस्थित थे।

छग विस के सदस्य करेंगे महाकुंभ में स्नान

■ डा. रमन ने मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष समेत सभी विधायकों और सांसदों को लिखा पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सहित समस्त मंत्रिमंडल के सदस्यों, नेता प्रतिपक्ष एवं सभी विधायकों व सांसदों (लोकसभा व राज्यसभा) को 13 फरवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने पत्र लिखकर कहा है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर आयोजित धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करते हुए सनातन लोकतांत्रिक परंपराओं का सजीव अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने लिखा कि इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने भी छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया है। दोनों राज्यों के विधायकों और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से यह आयोजन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से और भी ऐतिहासिक होगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सभी सांसदों से अनुरोध किया है कि वे अपनी सहमति संतोष पांडेय (सांसद, राजनांदगांव) के माध्यम से सहमति पत्र अथवा टेलीफोन द्वारा उपलब्ध कराएं। वहीं, सभी विधायकों को श्री सुशांत शुक्ला (विधायक, बेलतरा) के पास अपनी सहमति पत्र या फोन के माध्यम से भेजने का आग्रह किया गया है। इस पत्र में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने लिखा कि महाकुंभ न केवल आस्था का संगम है, बल्कि यह सनातन संस्कृति एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का जीवंत प्रतीक भी है। छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों की इसमें सहभागिता राज्य की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकता को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

आबकारी सचिव ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

अवैध मदिरा और मादक पदार्थों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

रायपुर। आबकारी विभाग की सचिव सह आयुक्त आर संगीता ने नवा रायपुर में विभागीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन, उड़नदस्ता दल और विभिन्न जिलों के आबकारी अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा और राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक के निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की सापेक्ष प्रगति की समीक्षा की और आगामी महीनों के लिए जिलेवार विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

आबकारी सचिव संगीता ने स्थानीय चुनावों के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी थाना एवं जांच चौकियों में सतर्कता बढ़ाने और विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया।

आबकारी सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री नहीं हो। उन्होंने ग्राहक सुविधा एवं शिकायत समाधान पर विशेष ध्यान देने के लिए मनपसंद मोबाइल ऐप और टोल-फ्री नंबर 14405 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए।

आबकारी सचिव ने फील्ड में कार्यरत आबकारी आरक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और इसके लिए जिला स्तर पर समन्वय कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही, मदिरा दुकानों में निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री न हो और मदिरा में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो, इसे कड़ाई से सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। सचिव ने कहा कि मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान किया जाए तथा बिक्री से प्राप्त राशि को बैंक में नियमानुसार जमा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस कार्य में लापरवाही पाई गई, तो संबंधित कैश कलेक्शन और बैंक एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति एवं न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निराकरण हेतु भी आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक श्याम लाल धावड़े, विशेष सचिव (आबकारी) देवेंद्र सिंह भारद्वाज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

निकाय चुनाव में प्रत्याशी ले रहे तंत्र-मंत्र का सहारा!

काले कपड़े में श्मशान घाट पहुंचे थे दो युवक, तांत्रिक क्रिया करते स्थानीय लोगों ने पकड़ा

रायपुर। नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी अपनी जीत के लिए तरह-तरह के उपाय अपना रहे हैं। ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला रायपुर के अमलीडीह इलाके से सामने आया है, जहां श्मशान घाट में चुनाव में प्रभाव डालने तांत्रिक क्रिया की गई। यहां स्थानीय लोगों ने दो युवकों को श्मशान घाट में तंत्र क्रियाएं करते देखा। अब इस घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।

वार्ड क्रमांक 50 के अमलीडीह श्मशान घाट में रात के अंधेरे में दो युवकों को काले कपड़े पहने हुए देखा गया। स्थानीय लोगों ने इन युवकों से पूछताछ की, लेकिन दोनों ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया और मौके से भाग गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यह दोनों तंत्र क्रियाएं कर रहे थे और इनका उद्देश्य चुनाव प्रभावित करना था। इस घटना के बाद भाजपाइयों ने युवकों पर तंत्र-मंत्र से चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बार-बार पूछने पर दोनों ने अपनी पहचान नहीं बताई।

इस मामले में भाजपा नेता उमेश घोरमोड़े का कहना है कि इस वक्त पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल है। इस बीच आधी रात युवकों को ऐसी स्थिति में पाया जाना मतदाताओं को अच्छा संदेश नहीं देता। राजनीतिक दलों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देश में लोकतंत्र है और जनता अपना मत निष्पक्षता से दे, यह जरूरी है। चुनाव के बीच ऐसी बातें सामने आना राजनीतिक दलों के लिए अच्छा नहीं है।

कांग्रेस नेता धनंजय ठाकुर का कहना है कि जो वीडियो जारी किया गया है उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी ऐसे कृत्य में संलिप्त नहीं है। बीजेपी को हार का डर है। वह पूरी तरह से डरी हुई है और इसी कारण ऐसे आरोप लगा रही है। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि बीजेपी की विश्वसनीयता जनता से जा चुकी है इसलिए ऐसे बेतुके आरोप लगा रही है।

इस मामले में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ। दिनेश मिश्रा ने कहा कि तांत्रिक क्रिया करके कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता है। ये सिर्फ मन का भ्रम और अंधविश्वास है। ऐसा करके कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता है। अगर ऐसा होता तो हर तांत्रिक यही करता।

धान खरीदी पर सियासत

कांग्रेस की वजह से मिला समर्थन मूल्य : भूपेश कांग्रेस किन बातों का लेगी क्रेडिट : साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव से पहले धान खरीदी में समर्थन मूल्य पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष की कांग्रेस पार्टी और सत्ताधारी भाजपा जनता का भरोसा जीतने में लगे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आज चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि किसानों को 3100 रुपए समर्थन मूल्य कांग्रेस की वजह से मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि किसानों को मेहनत का सम्मान मिलना चाहिए। भूपेश सरकार ने किसानों को 2850 समर्थन मूल्य दिया। किसानों को अब 31 सौ समर्थन मूल्य मिल रहा है तो यह कांग्रेस सरकार की वजह से मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस सरकार बनती तो 3217 रुपए समर्थन मूल्य किसानों को मिलता।

वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने उनके इस बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को 2003 से पहले का समय याद नहीं है। किसानों के धान को रिजेक्ट कर दिया जाता था। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की सुव्यवस्था भाजपा की सरकार में आई है। किसानों को समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि देने की शुरुआत भाजपा ने की।

डिप्टी सीएम साव ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हर एक बात पर 5 साल झूठ बोला। कांग्रेस किन बातों का क्रेडिट लेगी।? कांग्रेस को उनके कार्यकाल में हुए घोटालों का श्रेय लेना चाहिए।

क्या एआई रेस में आगे निकल जाएगा चीन?

संकल्प सिंह

अक्तूबर 4, 1957 सोवियत संघ स्पूतनिक 1 (पृथ्वी की पहली सैटलाइट) अंतरिक्ष में लॉन्च करता है। यूएसएसआर के इस एक कदम से पूरे अमेरिका में हलचल मच जाती है। स्पूतनिक संकट ने पूरे अमेरिका में डर का माहौल बना दिया था। अमेरिका को लगा की जब सोवियत संघ आईसीबीएम तकनीक की मदद से स्पूतनिक 1 को अंतरिक्ष में भेज सकता है, तो वह इसकी मदद से अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। इसके बाद 1958 में अमेरिका ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) की स्थापना की, ताकि अंतरिक्ष में सोवियत संघ को टक्कर दी जा सके, फिर जो हुआ वह इतिहास बनकर रह गया। कुछ ऐसा ही इन दिनों भी हो रहा है, लेकिन इस बार ये लड़ाई अंतरिक्ष में नहीं बल्कि तकनीक की दुनिया में हो रही है। स्पूतनिक 1 ने अमेरिका में जो हलचल पैदा की थी कुछ उसी तरह का डर चीन के डीपसीक एआई ने इन दिनों अमेरिका में फैला दिया है। ट्रंप के सत्ता में आते ही चीन ने डीपसीक नाम के एक एआई टूल से अमेरिका के गुरूर पर हमला किया है। इस एआई टूल के लॉन्च करने के कुछ ही समय के भीतर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनविडिया को करीब 600 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। एनविडिया के साथ-साथ मेटा, टेस्ला, गूगल और कई दूसरी कंपनियों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस एआई टूल ने लॉन्च होने के बाद ग्लोबल एआई मार्केट के नियम कायदे ही बदल दिए हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया अब एक नए शीतयुद्ध के दौर में प्रवेश कर चुकी है। यह शीतयुद्ध बिल्कुल अलग है। इसे तकनीक के स्तर पर लड़ा जा रहा है। यहां लड़ाई बम और बारूद से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा और इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर हो रही है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये डीपसीक एआई, जिसने लॉन्च होने के कुछ दिनों के भीतर ही अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि आखिर कैसे चीन, अमेरिका द्वारा एडवांस कंप्यूटिंग चिप्स के निर्यात पर बैन लगा दिए जाने के बाद भी इस तरह की तकनीक को बनाने में सफल हुआ? डीपसीक एक एआई पावर्ड चैटबॉट है। इसके काम करने का तरीका काफी हद तक चैटजीपीटी जैसा ही है। रिपोर्ट के अनुसार इसके काम करने की शक्ति ओपन एआई के ०1 मोडल जैसी है, जिसे पिछले साल के अंत में जारी किया गया था। इसे चैटजीपीटी की तुलना में काफी कम जीपीयू का इस्तेमाल करके ट्रेन किया गया है। डीपसीक एआई डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए चैटजीपीटी की तुलना में बहुत कम जीपीयू का इस्तेमाल करता है। खास बात यह है कि कम जीपीयू का इस्तेमाल करके भी डीपसीक एआई, चैटजीपीटी जैसा ही कार्यकुशल है। यही नहीं कई बेंचमार्क्स पर इसने चीटजीपीटी, गूगल और मेटा के एडवांस एआई मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। डीपसीक के सबसे लेटेस्ट ऋ मोडल को केवल 5.6 मिलियन डॉलर के बजट पर ट्रेन किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस एआई टूल को बनाने में जितनी लागत आई है, वह अमेरिकन एआई मॉडल को बनाने के खर्च की तुलना में कई गुना कम है। एक तरफ जहां यूजर्स को चैट जीपीटी प्लस का उपयोग करने के लिए 20 डॉलर खर्च करना पड़ता है, उसकी तुलना में डीपसीक एआई का उपयोग करने के लिए आपको किसी प्रकार के पैसों को खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। यही नहीं डीपसीक ने दुनियाभर में हर किसी के लिए अपना एक ओपनसोर्स भी जारी कर दिया है। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है, जिसमें अच्छा खासा जीपीयू लगा हुआ है, तो डीपसीक को आप अपने ही लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए न तो आपको डीपसीक के चैट सर्वर में जाना होगा और न ही आपको इंटरनेट की जरूरत होगी। इस सर्विस के लिए आपसे कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। खास बात यह है कि चीन ने डीपसीक एआई के अल्गोरिदम को छुपाया नहीं है इसको ओपन सोर्स कर दिया है। इस कारण दुनियाभर में इस एआई टूल का कई तरह के पैरामीटर्स पर परिक्षण किया जा रहा है। कई विशेषज्ञों द्वारा यह कहा जा रहा है कि डीपसीक एआई कई एआई मॉडल्स की तुलना में बेहतर ढंग से काम करता है वो भी बिना ज्यादा महंगे जीपीयू और हार्डवेयर की जरूरत लिए। डीपसीक सिर्फ एक एआई टूल नहीं बल्कि यह भविष्य की झलक है, जहां शक्ति संतुलन मिसाइलों, एयरक्राफ्ट, बड़े-बड़े टैंकों में नहीं बल्कि अल्गोरिदम में छिपा होगा। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा यह तकनीकी शीतयुद्ध अब एक रोमांचक मोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है। 1957 में स्पूतनिक 1 के लॉन्च ने अमेरिका को एक होड़ में धकेला था, जिसके नतीजे में इंसान पहली बार चांद पर कदम रख पाया।

अवैध प्रवासियों को भारत भेजना नयी बात नहीं

शशांक

अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 104 भारतीयों के एक समूह को वहां के प्रशासन ने सैन्य विमान से भारत भेज दिया। इन भारतीयों को लेकर अमेरिका का सैन्य विमान बुधवार को अमृतसर उतरा। ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी उन नीतियों पर अमल करना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में वे अपने चुनाव के दौरान लगातार बोल रहे थे। अमेरिका में जितने भी अवैध प्रवासी हैं, उन्हें वे वहां से निकालना चाहते हैं।

हालांकि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने जितने भी अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकाला था, उसकी तुलना में यदि हम एक डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति का कार्यकाल देखें, विशेषकर बराक ओबामा का, तो अपने समय में उन्होंने दोगुने लोगों को निकाला था। ट्रंप के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डब्ल्यू बुश की बात करें, तो उन्होंने भी ट्रंप से कहीं अधिक अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाला था। लिहाजा, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। मुझे याद आता है, जब इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गनाइजेशन थी, तो वहां 1980 के दशक में मैं भी गया था, वहां अवैध प्रवासियों को लेकर जो चर्चा होती थी, तो हमारा और अमेरिका का रवैया लगभग एक जैसा ही होता था कि हम अवैध प्रवासियों को अपने यहां रहने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

हालांकि हमारे जो मुद्दे हैं, वे अमेरिका के अलग हैं। अमेरिका को लगता है कि अवैध प्रवासी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। दूसरा, उनको लगता है कि वे नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि केवल भारत को ही अकेला निशाना बनाया गया है। अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने के लिए ट्रंप प्रशासन ने मेक्सिको की सीमा पर अपने सीमा प्रहरियों, सेना को लगा दिया है। इसी तरह से फेडरल ट्रूप्स को वे सभी राज्यों में, विशेषकर डेमोक्रेटिक या उन राज्यों में, जो अधिक उदारवादी रहे हैं, भेज रहे हैं, जिनको अवैध प्रवासियों व सस्ते श्रमिकों की जरूरत थी। ट्रंप का मानना है कि इन राज्यों ने अवैध प्रवासियों को अमेरिका में रहने के लिए प्रोत्साहित किया है।

ट्रंप अवैध प्रवासियों को लेकर इतने गंभीर हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि उनके फेडरल ट्रूप्स या फेडरल डिपार्टमेंट उन राज्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने अवैध प्रवासियों को बसाने में मदद की है। पिछली बार से इस बार बस इतना अंतर है कि इस बार उन्होंने अवैध प्रवासियों को संबंधित देश में भेजने के लिए चार्टर प्लेन की जगह सैन्य विमान का इस्तेमाल किया है। यह बात भारत समेत कई देशों को खली है। अमेरिका के जो साझेदार देश हैं, उन्होंने इसे लेकर प्रश्न भी उठाया है।

प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर अवैध प्रवासियों की वापसी के लिए किराये का भुगतान कौन करेगा। यदि किराये का भुगतान भारत करता है, तो उसे अवैध प्रवासियों से कहना होगा कि वे तब तक दोबारा देश से बाहर नहीं जा सकते, जब तक वे अपना पैसा चुका नहीं देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अमेरिकी सरकार लोगों के यहां आने का खर्च दे। हालांकि यह बात अमेरिका के ऊपर है कि वह इसे मानता है या नहीं। अब जब 104 भारतीयों का एक समूह अमेरिका से वापस भेज दिया गया है, तो इसके बाद भारत सरकार को अमेरिका में रह रहे लोगों से बातचीत करनी चाहिए कि जो लोग भारत सरकार के खर्चे पर वापस आना चाहते हैं, उनके लिए सरकार चार्टर प्लेन भेज देगी, लेकिन वे दोबारा तब तक बाहर नहीं जा पायेंगे, जब तक सरकार का पैसा नहीं लौटा देते। तो जिनको सरकार का यह प्रस्ताव पसंद आता है, वे चार्टर प्लेन में सरकार के खर्चे पर भारत आ सकते है या फिर यह भी हो सकता है कि अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय, राजनीतिक दलों के ओवरसीज ग्रुप पैसा इकट्ठा कर अपने लोगों को देश वापस भेज दें।

व्यापार संबंधों की यदि बात करें, तो अमेरिका के अधिकांश देशों के साथ एडवर्स ट्रेड हैं यानी दूसरे देशों के साथ उसका व्यापार घाटा अधिक है। इसे देखते हुए ट्रंप हमेशा नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। यहां मुझे दो बातें कहनी हैं। पहली यह कि भारत जो सामान अमेरिका को बेचता है, वह अधिकतर लघु उद्योगों के उत्पाद होते हैं या फिर एमएसएमइ क्षेत्र के होते हैं और हम अमेरिका से जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (जीएसपी) मांगते हैं। ये चीजें बहुत कम शुल्क के साथ उनको बेची जाती हैं। हालांकि यह बात और है कि अमेरिका के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी थी, तब भी ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में हमारा जीएसपी बंद कर दिया था, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ यह चालू था। तो, यहां जीएसपी के लिए बातचीत की जा सकती है। दूसरी बात, हम अमेरिका के साथ जो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वह केवल सेवा क्षेत्र में ही कर रहे हैं। अमेरिका के सेवा क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय भी चाहते हैं कि वे शांतिपूर्वक काम करें। भारत भी चाहता है कि अमेरिका उन्हें शांतिपूर्वक काम करने दे। ऐसे में भारत सरकार अमेरिका से बातचीत कर इसका हल निकाल सकती है कि हमारे लोग जो वहां काम कर रहे हैं, उन्हें फिलहाल काम करने दिया जाए। हम धीरे-धीरे अपने लोगों को वापस बुला लेंगे, पर यह सब व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए और इसके लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

अमेरिका अपने व्यापार घाटे को लेकर परेशान है और इसी कारण वह अपने यहां आयात होने वाली वस्तुओं पर भारी शुल्क लगा रहा है। यहां अमेरिका से पारस्परिक हितों को ध्यान में रखते हुए बात की जा सकती है। यदि एडवर्स ट्रेड है, तो हम अमेरिका से ड्यूटी फ्री व्यापार के बारे में बात कर सकते हैं कि उसके हितों से जुड़े जो सामान हैं, हम उनमें से कुछ पर शुल्क कम कर देंगे और वे हमारे उत्पादों पर शुल्क न बढ़ाए। व्यापार के मामले में भारत का दो तरफा तरीके से बात करना बेहतर होगा, क्योंकि हम अमेरिका से अपने रिश्ते और प्रगाढ़ करना चाहते हैं, रिश्तों में गिरावट नहीं चाहते हैं। चीन, मेक्सिको, कनाडा का अपना तरीका है। हालांकि मेक्सिको और कनाडा को एक महीने का समय मिल गया है। तो हम भी उनसे अधिक समय मांग सकते हैं। कुल मिला कर भारत का विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, बिजनेस एसोसिएशन सभी व्यवस्थित और संगठित तरीके से अमेरिका से शुल्क को लेकर बात करें, तो चीजें सुलझ सकती हैं, क्योंकि हमें अपना व्यापार बढ़ाना है, कम नहीं करना। बातचीत के लिए समय ले लेना चाहिए और नियमित अंतराल पर बातचीत करते रहना चाहिए।

एकात्मता के स्वर — वेद

वेदों का भारतीय समाज जीवन में अद्वितीय महत्व रहा है। वह हमारे समाज के लिए पुरातन समय से ही धर्म, कर्म, दर्शन और संस्कृति के उद्गाता रहे हैं। कहा है वेदो ऽखिलो मूलम्। वेद सभी धर्मों का मूल हैं।

केवल भारत ही नहीं विश्व में जितने भी धर्म हैं वह उन सबकी जड़ है और वेद ही वेदो ऽखिलो ज्ञानमूलम्। मु। सभी प्रकार के ज्ञान का मूल है। वेद की उत्पत्ति के संदर्भ में श्रीमद्भागवत महापुराण में कहा है कि परमेष्ठी ब्रह्मा जी के हृदयाकाश से कंठ-तालु आदि स्थान के संघर्ष से रहित एक विलक्षण अनाहत नाद उत्पन्न हुआ। उसी अनाहत नाद से अ कार, उ कार और म कार रूप तीन मात्राओं से युक्त कार प्रकट हुआ। ओमकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिवर्तित हो जाती है। ओमकार ही परमात्मा का वाचक, मंत्र, उपनिषद् और वेदों का सनातन बीज है। स सर्वमन्त्रोपनिषद्धेदबीजं सनातनम् ।। 12/6/41 सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने तेनासी चतुरो वेदांश्चतुर्भिर्वदनैर्विभुः। सव्याहृतिकान् सोकारंश्चातुर्होत्रविवक्षया।। 12/6/44 अपने चारो मुखों से अतुल ज्ञानराशि ओमकार और व्याहृतियों के सहित चार वेद प्रकट किये और अपने पुत्र मरीचि आदि को वेदाध्ययन कुशल देखकर वेद की शिक्षा दी। यह वेदज्ञान श्रुति के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। जब ब्रह्मवेता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गयी है तब द्वापर के अंत में श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास ने मंत्र समुदायों में से भिन्न-भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके ऋ, यजुः साम और अथर्व ये चार संहिताएँ बनायीं और अपने चार शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक-एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने ब्रह्मच नाम की पहली ऋक्संहिता पैल को, निगद नाम की दूसरी यजुः संहिता वैशम्पायन को, सामश्रुतियों की छान्दोग्य-संहिता जैमिनि को और समंतु को अथर्वांगिरसिहिता का अध्ययन कराया। आगे इनके शिष्यों ने भी संहिता के अनेक भाग किये और अपने शिष्यों को पढ़ाया।

ऋग्वेद में दश मण्डल चौसठ अध्याय दश सौ अठ्ठाईस सूक्त तथा दस हजार पांच सौ बावन मंत्र हैं। यजुर्वेद में चालीस अध्याय तीन सौ तीन अनुवाक् तथा उन्तीस सौ पचहत्तर कंडिका (मंत्र) हैं। इसके दो भाग हैं, शुक्लयजुर्वेद और कृष्णयजुर्वेद। सामवेद में अठराह सौ पचहत्तर मंत्र हैं। पचहत्तर को छोड़ सभी ऋग्वेद से लिये गये हैं। अथर्ववेद में बीस काण्ड सात सी इकतीस सूक्त तथा पाँच हजार नौ सौ सत्तर मंत्र हैं। वेदों के द्रष्टा केवल ऋषि ही नहीं थे, अपितु महिलाएँ भी मंत्र द्रष्टा थीं।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

जो विलासिता, जो कर्तव्यपराङ्मुखता विचारे पुरंजन के सिर पर लदी थी वह सब की सब अपने आप में दीख पड़ती है और जो दशा तथा दुर्गति पुरंजन की हुई थी उससे भी शतगुनी आपत्ति का पहाड़ अपने मस्तक पर टूट पड़ता हुआ नजर आता है।

उस समय अन्तरात्मा कह उठता है कि यह पुरंजन अण्य कोई नहीं, तू ही पुरंजन है, यह सध सन्दर्भ तेरे ही जीवन का सच्चा फोटो है। अगले अध्याय में व्यास जी स्वयं इस लोकभाषा का भांडा फोड़ करते हुये निम्नलिखित सूचना दे देते हैं कि-

(ख) पुरुषं पुरंजनं विद्यात् पुरुषस्य सखेश्वरः। बुद्धिन्तु प्रमदां विद्यात् संवत्सरश्चण्डवेगः।। कालकन्या जरा साक्षात्... प्रज्वारो द्विविधोज्वरः। स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः।। (श्रीमद्भागवत 4 । 36 अध्याय)

अर्थात्- यह जीत्र ही पुरंजन है, ईश्वर इसका आज्ञात मित्र है। उक्त जीव अनेक योनियों में भटकता हुआ अपने अनुकूल देहरूप नगर को ढूंढता फिरता है। दो आंखें, दो ना के छिद्र और दो कान मुख, लिङ्ग और गुदा इन नौ छिद्रों वाला मनुष्य शरीर ही सुन्दर नगर है, जिसे यह अपना लेता है। मनुष्य दह रूप नगर में आते ही जीव को बुद्धिरूपिणी स्त्री दीख पड़ती है। दशों इन्द्रियाँ ही इस पुरंजनी के सेवक हैं, जो सेंकड़ों प्रकार के इन्द्रिय कार्यों के अधिनायक हैं। पांच वृत्तियों वाला प्राण ही पञ्चशीर्ष सर्प है जो प्रतिहारी की तरह इसे सब भांति सुरक्षित रखता है। इस प्रकार जीव और बुद्धिरूप दम्पति मनुष्य देह नगर में आनन्द उपभोग करते हैं।

आँख नाक आदि सात ऊपर के दर्वाजे हैं और लिङ्ग गुदा रूप दो नीचे की ओर। जीव बुद्धि के आदेशानुसार सब क्रियाएं दरने लगता है।

क्रमशः ...

गजल सम्राट जगजीत सिंह

अनन्या मिश्रा

पूरी दुनिया में अपने सुरों को लेकर फेमस जगजीत सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज ही के दिन यानी की 8 फरवरी को जगजीत सिंह का जन्म हुआ था। गजल गायकी की दुनिया में जगजीत सिंह का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। भले ही आज वह हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनके गजलों को हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। इसी कारण उनको गजल किंग भी कहा जाता है। वहीं बॉलीवुड के तमाम गीतों को उन्होंने अपनी मखमली आवाज से सजाने का काम किया था।

राजस्थान के श्रीगंगानगर में 8 फरवरी 1941 को जगजीत सिंह का जन्म हुआ था। उनकी शुरूआती पढ़ाई श्रीगंगानगर से शुरू हुई। बाद में वह उच्च शिक्षा के लिए जालंधर चले गए। जगजीत सिंह के पिता का नाम अमर सिंह धमानी था, वह सरकारी कर्मचारी होने के साथ ही संगीत में भी रुचि रखते थे। जगजीत सिंह को अपने पिता से संगीत विरासत में मिला था। इनका असली नाम जगमोहन सिंह धीमान था।

गजल की दुनिया में अपना नाम कमाने वाले जगजीत सिंह की जिंदगी मुश्किलों भरी रही। भले ही उनके पिता संगीत में रुचि रखते थे, लेकिन वह चाहते थे कि जगजीत सिंह पढ़-लिखकर बड़े अफसर बनें। उनके पिता फिल्मों में गाना गाए जाने को लेकर भी खिलाफ थे। ऐसे में संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए जगजीत सिंह को घर छोड़कर भागना पड़ा।

अपने सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे जगजीत सिंह को गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दो वक्त की रोटी के लिए वह दर-दर की ठोकरें खाते थे। दो वक्त के खाने के लिए वह होटल में गाना गाया करते थे। काफी संघर्ष के बाद जगजीत सिंह को पहली उम्मीद तब दिखी, जब उनको पहली गुजराती फिल्म में गाना गाने का ऑफर मिला।

आपको बता दें कि साल 1967 में जगजीत सिंह की मुलाकात गजल गायिका चित्रा से हुई। चित्रा से उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। साल 1969 में वह दोनों शादी के बंधन में बंध गए। वहीं जगजीत और चित्रा एक साथ कई गजल समारोह में समां बांधते थे। उन दोनों की जुगलबंदी देखने लायक होती थी। वहीं इस कपल का एक बेटा विवेक था।

जगजीत सिंह के करीबियों की मानें, तो गजल सम्राट की गजलों में उनकी तड़प व दुख साफ दिखाई देता था। उन्होंने साल 1976 को पहली एलबम %द अनफॉरगेटेबल्स% रिलीज की, जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद उनको कभी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। फिल्मों में गजलें गाने की शुरूआत करने के बाद जगजीत सबकी पहली पंसद हुआ करते थे।

'तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो', 'तुमको देखा तो ये ख्याल आया', 'झुकी-झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं', 'प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है', 'होश वालों को', 'ये दौलत भी ले लो', 'चिट्ठी न कोई संदेश' और 'होठों से छू लो तुम' उनकी खास गजलों में शामिल हैं। करीब 150 से ज्यादा एल्बम में जगजीत सिंह ने अपनी गजलों को खूबसूरत बनाने का काम किया।

ट्रंप और वैश्वीकरण की सांसें, हावी रही अमेरिकी चकाचौंध

बलबीर पुंज

गत बुधवार (5 फरवरी) अमेरिका से 104 अवैध प्रवासी भारतीय बेइज्जत होकर अमेरिकी सैन्य विमान से स्वदेश लौटे। इन सबकी चालीस घंटे की यात्रा कितनी अपमानजनक रही होगी कि उन्हें हथकड़ी और बेड़ियों से बांधा गया था। ये दुर्भाग्यशाली लोग बेईमान ट्रैवल एजेंटों, अपने लालच और रातोंरात अमीर बनने की चाह के शिकार थे। यह ध्यान रहे कि इनमें से कोई भी बदहाल गरीब नहीं था। अमेरिका जाने हेतु उन्होंने जिस गैर-कानूनी मार्ग को अपनाया, उसके लिए उन्होंने 50 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक खर्च किए थे।

यह कोई पहली बार नहीं है कि जब अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीय स्वदेश लौटे हों। गत वर्ष अक्तूबर में एक अमेरिकी चार्टर्ड विमान से 100 लोग पंजाब वापस भेजे गए थे। कुल मिलाकर अक्तूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 के बीच 1100 अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिका ने चुपचाप स्वदेश भेजा था। इस बार अंतर केवल इतना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रक्रिया को अत्यधिक नाटकीय बनाते हुए महंगे सैन्य विमानों का उपयोग किया है। निस्संदेह, यह घटनाक्रम भारत के लिए शर्मिंदगी का विषय है। यह सब अमेरिका में वैध रूप से जीवनयापन कर रहे 50 लाख भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को भी असहज करता है, जो अपनी प्रतिभा, शिक्षा, योग्यता और संस्कृति से जुड़ाव के कारण सफल हैं। इस भारतीय समूह की औसत घरेलू आय 1,45,000 डॉलर है, जो अमेरिका की राष्ट्रीय औसत आय 80,610 डॉलर से कहीं अधिक है। आखिर क्यों विकासशील देशों के लोग

बड़ी संख्या में अमेरिका जाना चाहते हैं? जिस अमेरिका को हम जानते हैं, उसे वर्ष 1492-93 में यूरोपीय ईसाई प्रचारक क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत समझकर अनजाने में खोजा था। जहां यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने विस्तारवाद और मजहबी दमनचक्र चलाकर अमेरिका के मूल ध्वजवाहकों और उनकी संस्कृति को संग्रहालय की शोभा बढ़ाने तक सीमित कर दिया, तो इसी अवधि में वे यूरोप से अमेरिका में आर्थिक-बौद्धिक पूंजी का निवेश करते रहे। अमेरिकी जनगणना के अनुसार, वर्ष 1610 में गैर-मूलनिवासी 'उपनिवेशवादियों' की आबादी केवल 500 थी, जो 1780 में बढ़कर लगभग 28 लाख हो गई। इसके आठ साल बाद नए राष्ट्र 'संयुक्त राज्य अमेरिका' का संविधान अस्तित्व में आया।

अमेरिका की आबादी 34 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का केवल एक चौथाई हिस्सा है। अमेरिका का भू-भाग भारत से तीन गुना बड़ा है। इसके पास 95,000 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है, तो 256 अरब बैरल कच्चे तेल के भंडार हैं, जो सऊदी अरब से भी अधिक है। अमेरिका वैश्विक 45 प्रतिशत पानी, 22 प्रतिशत कोयला, छह प्रतिशत जमीन, दस प्रतिशत कृषि योग्य भूमि और मात्र चार प्रतिशत जनसंख्या के साथ दुनिया का संपन्न देश है। उसकी सीमाएं भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन, भारत-बांग्लादेश या फिर यूरोप-रूस जैसी जटिल और तनावग्रस्त नहीं हैं। ईरान, चीन और रूस जैसे 'शत्रु राष्ट्र' अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर हैं। अमेरिका की यही विशेषता विकासशील देशों के कई लोगों को आकर्षित करती है। मौजूदा स्थिति को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बदलना चाहते हैं। उनकी नीति अपने देश को उन मूल्यों से अंगीकृत करना है, जिसमें केवल अमेरिका और उसके मूल नागरिकों के लिए स्थान हो। इसी शृंखला में ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेशों से विश्व में 'शुल्क युद्ध' भी प्रारंभ कर दिया। जैसे ही एक फरवरी को अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 25 प्रतिशत व चीन पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लागू किया, वैसे ही कनाडा-मेक्सिको ने पलटवार करते हुए अमेरिकी आयातित वस्तुओं पर भी अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। हालांकि, ट्रंप ने बाद में एक समझौते के तहत कनाडा-मेक्सिको को इससे राहत दे दी। ट्रंप ब्रिक्स समूह (भारत सहित) को भी व्यापारिक लेन-देन में अमेरिकी डॉलर का विकल्प ढूंढने पर चेतावनी जारी कर चुके हैं। इसी पृष्ठभूमि में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वैश्वीकरण, जिसका जन्म द्वितीय विश्वयुद्ध (1939-45) के बाद हुआ था-उसके ताबूत में ट्रंप अपनी नीतियों से अंतिम कील ठोक रहे हैं।

विचारों के संसार में वैश्वीकरण की आयु अब तक सबसे कम है, जिसका दशकों तक अमेरिका पर्याय और संरक्षक रहा है। भारत की सनातन परंपरा छोड़ दें, तो मजहब के रूप में यहूदी तीन हजार से अधिक, ईसाइयत दो हजार, तो इस्लाम 1400 वर्षों से है। वामपंथ ने 74 वर्षों (1917-91) में दम तोड़ दिया। वर्तमान समय में चीन का वैचारिक-राजनीतिक अधिष्ठान वामपंथी, तो आर्थिकी पूंजीवादी है। उत्तर कोरिया, लाओस, वियतनाम, क्यूबा भी साम्यवादी देश हैं और इनमें से कोई भी दुनिया में पूरी तरह खुशहाल और आदर्श समाज की परिकल्पना साकार नहीं कर पाया है। दुनिया में 'आदर्श समाज' कैसा हो और आर्थिकी के मानक कैसे हों, इस पर भी 'व्हाइट मेन बर्डन' चिंतन से प्रेरित अमेरिका और पश्चिमी देशों का एकतरफा नियंत्रण रहा है। जब अमेरिका और यूरोपीय देशों के समर्थन से वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ, तब उसके सामाजिक-आर्थिक विभाग ने वर्ष 1951 में 'वन मॉडल, फिट्स ऑल' शेष विश्व पर थोपते हुए कहा, 'ऐसा अनुभव होता है कि तीव्र आर्थिक प्रगति बिना दर्दनाक समायोजन के संभव नहीं।

वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी के बाद अमेरिका सहित यूरोपीय देशों को अपनी गलती का बोध हुआ और वर्ष 2015 में किसी भी देश में विकास के लिए उसकी संस्कृति को आधार बताया। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने शासनकाल (2016-20 और 2025 से अबतक) में ट्रंप ने जो निर्णय लिए, वह संभवतः इसी परिवर्तन का मूर्त रूप हैं। इसलिए अमेरिका, जो स्वयं को वैश्वीकरण का झंडाबरदार समझता था-उसने इस वहम को त्याग दिया। विकासशील देशों के हजारों-लाखों लोग दशकों से अमेरिकी चकाचौंध से प्रभावित होते रहे हैं और लालच में वहां पहुंचने हेतु अवैध मार्ग भी अपना लेते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश से बाहर घी-चुपड़ी रोटी से कहीं गुना बेहतर घर में मिलने वाली संतोषप्रद और आरामदायक सूखी रोटी है। शायद 40 घंटे की लज्जित यात्रा करके और अपना सब कुछ गंवाकर स्वदेश लौटे 104 भारतीय यही सोच रहे होंगे।

आज का इतिहास

1922 अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउस ने रोडियो का उपयोग शुरू किया।
1933 टेक्सास में सबसे ठंडा तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया।
1950 पूर्वी जर्मनी की गुप्त पुलिस स्टासी की स्थापना की गई थी।
1952 महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी और राष्ट्रमंडल देशों की अध्यक्ष बनी।
1960 हॉलीवुड, लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में पहले आठ ब्रास स्टार पट्टिका हॉलिवुड वॉक ऑफ फ़ेम में स्थापित की गई थीं।
1968 ऑरेंजबर्ग, दक्षिण कैरोलिना में स्थानीय पुलिस ने भीड़ के लोगों को निकाल दिया, जो अलगाव का विरोध कर रहे थे, जिसमें तीन लोग मारे गए और सात अन्य घायल हो गए।
1971 दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार नैस्डैक की शुरुआत हुई।
1978 अमेरिकी सीनेट की कार्यवाही को पहली बार रेडियो पर प्रसारित किया गया।
1979 जॉशिम योम्बी-ओपांगो के सत्ता से हटने के बाद डेनिस सासो न्यूस्सो को कांगो गणराज्य का नया राष्ट्रपति चुना गया।
1992 यूलिसिस अंतरिक्षयान बृहस्पति ग्रह के निकट से गुजरा।
1993 सुचोई की दुर्घटना में 134 निर्दोष यात्रियों की मौत - 24 टुपोलर यात्रियों की उड़ान में।
1994 जैक निकोलसन द्वारा एक कार पर हमला किया गया था और उन्होंने कार पर हमला करने के लिए एक गोल्फ क्लब का उपयोग किया था।
1995 टूजिलो में 6.4 के पैमाने के साथ आए भूकंप में 46 निर्दोष लोग मारे गए थे।
1998 ओलंपिक इतिहास में पहली महिला आइस हॉकी खेल में फिनलैंड ने स्वीडन को लगभग 6-8 अंकों से हराया जो कि बहुत बड़ा नुकसान था।
2004 46 वें गामी पुरस्कार के प्रमुख पुरस्कार कोल्ड प्ले, आउट कास्ट, रिचर्ड मैन, लेदर वैंड्रॉस क्रिस्टीना एगुइलेना और जस्टिन टिम्बर लेक द्वारा जीते जाते हैं।

अमेरिका-चीन में पुनः शुरू हुए व्यापार युद्ध

कमलेश पांडे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम भारतीयों के मनोमस्तिष्क में इसलिए हमेशा बसे रहते हैं कि उन्होंने आपदा को अवसर में बदलने का हुनर दिखलाया-सिखलाया-बतलाया है। इस हेतु राष्ट्रीय जज्बे को जिस शानदार-जानदार तरीके से उन्होंने प्रदर्शित किया-करवाया है, उसने हम सबको उनका मुरीद बना दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना के पहले, कोविड-19 के दौरान और उसके बाद भी उन्होंने दुनियावी त्रासदी/पारस्परिक संघर्षों-संकटों को जितना सकारात्मक तरीके से लिया है, उससे भारत पुनः विश्वगुरू बनने की ओर अग्रसर है। उनके नेतृत्व में भारत अब याचक कम, दाता ज्यादा नजर आता है।

यही वजह है कि समावेशी व्यापार प्रचलन स्थापित-संचालित-नियंत्रित करने में विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की विफलता के बाद दुनिया के देशों में मचे व्यापार युद्ध मतलब टैरिफ वॉर से उतपन्न होने वाले द्विपक्षीय कारोबारी आपदा को तीसरे पक्ष हेतु अवसर में बदलने के लिए भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं और उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस विषय पर हम यहां चर्चा करेंगे। क्योंकि आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध भारतीय निर्यातकों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

समझा जाता है कि अमेरिका-चीन जैसे दो बड़े देशों के इस अप्रत्याशित कदम से अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, आंकड़ा जन्य अनुभव बताता है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल (2016-2020) के दौरान जब अमेरिका ने चीनी चीजों पर टैरिफ लगाया था, तो उस दौरान भारत चौथा सबसे बड़ा फायदा पाने वाला देश था। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है चीन से आयात पर अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जाने से भारत को अमेरिका में निर्यात के लिए बहुत अवसर मिलेंगे। क्योंकि टैरिफ लगाए जाने से चीन से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर असर पड़ेगा।

बताया जाता है कि इससे अमेरिकी बाजार में उनके सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी। इससे अमेरिकी खरीदार उच्च लागत से बचने के लिए वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करेंगे। इससे भारत को फायदा होगा। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को एक इग्जेक्युटिव आदेश पर हस्ताक्षर किए। जिसमें मेक्सिको से आने वाले सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया। वहीं, कनाडा से आने वाले सामानों पर भी 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया। जबकि, कनाडा के ऊर्जा संसाधनों पर 10 प्रतिशत टैरिफ ही लगाने की घोषणा की गई। इस ऑर्डर में ही चीन से आयात पर भी 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात थी, जिससे चीन बौखला गया।

अलबत्ता, अमेरिका के जवाब में चीन ने भी कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगा दिया है। उसके इस जवाबी कदम के साथ ही दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। उधर, अमेरिकी कदम के जवाब में मेक्सिको और कनाडा ने भी अमेरिकी टैरिफ के बदले में जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इससे व्यापार युद्ध कई देशों के बीच पहुंच गया है। निकट भविष्य में इसके चक्कर में और कई देशों के आने की संभावना है। स्वाभाविक है कि इन सभी कदमों का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

बता दें कि इस बारे में अपनी सफाई देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि यह कदम अवैध इमिग्रेशन और ड्रग्स तस्करी से उपजी चिंताओं को लेकर उठाया गया है। क्योंकि रिपब्लिकन नेता ट्रंप ने इन दो मुख्य मुद्दों को अपने चुनावी अभियान का आधार बनाया था। चूंकि चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद से ही उनकी ओर से जनता से किये हुए वादों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए जाने के संकेत दिए जा रहे थे। इसलिए यह कदम उठाया गया है।

सवाल है कि चीन के अमेरिका पर टैरिफ लगाने का कितना प्रभाव उसपर पड़ेगा, तो जानकारों के मुताबिक जवाब यह होगा कि अमेरिका पर इसका सीमित प्रभाव हो सकता है। क्योंकि अमेरिका दुनिया में तरल प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, लेकिन उस निर्यात में चीन की हिस्सेदारी महज 2.3 फीसदी के आसपास है। वहीं, चीन का सबसे बड़ा कार आयात यूरोप और जापान से होता है। इसलिए विशेषज्ञ इसे चीन की सौदेबाजी की शक्ति हासिल करने के तौर-तरीके के रूप में इसे देख रहे हैं।

वहीं, जहां तक इस ट्रेड वॉर के चीन पर असर होने

का सवाल है तो जानकार बताते हैं कि चीन 120 से अधिक देशों के लिए प्रमुख व्यापार भागीदार है और अमेरिका उनमें से सिर्फ एक है। वहीं, पिछले दो दशकों में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में व्यापार के महत्व को लगातार कम किया है और घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी की है। यही वजह है कि आज आयात और निर्यात का चीन के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 37 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि 2000 के दशक की शुरुआत में यह 60 फीसदी से अधिक था। इसलिए 10 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ उसे सिर्फ चुभेगा, जबकि पेइचिंग इस झटके को बर्दाश्त कर सकता है। कुछ यही वजह है कि चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने भी अमेरिका के खिलाफ कई उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही गत मंगलवार को उसने अमेरिकी सर्च इंजन %गूगल% की जांच की भी बात कही, ताकि उसके कारोबारी हितों को चोट पहुंचाया जा सके। बताया गया है कि चीन द्वारा अमेरिकी कोयला और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) उत्पादों पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। साथ ही कच्चे तेल, कृषि मशीनरी, बड़ी कारों पर भी 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। वहीं, मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी उत्पादों पर नए टैरिफ 10 फरवरी से शुरू यानी प्रभावी होंगे।

वहीं, चीन की ओर से यह भी कहा गया है कि अमेरिका का एकतरफा टैरिफ बढ़ाना वर्ल्ड ट्रेड अऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों का घोर उल्लंघन है। यह उनकी समस्याओं को हल करने में कोई मदद नहीं करेगा। हां, इतना जरूर है कि यह चीन और अमेरिका के बीच सामान्य आर्थिक और व्यापार सहयोग को नुकसान पहुंचाएगा। चूंकि वैश्विक थानेदारी के लिए दोनों में आपसी होड़ मची हुई है, इसलिए यह स्वाभाविक कदम भी है। निकट भविष्य में कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं।

उधर, चीन के स्टेट ऐडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन ने यह भी कहा है कि वह गूगल पर विश्वास विरोध (एंटीट्रस्ट) कानूनों के उल्लंघन के संदेह में जांच कर रहा है। हालांकि, इसमें किसी टैरिफ का विशेष रूप से जिक्र नहीं किया गया। हालांकि, यह घोषणा वह ट्रंप के 10 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के कुछ ही मिनट बाद ही की गई।

बताया जाता है कि ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर कड़े टैरिफ लगाने संबंधी एक आदेश पर गत शनिवार को हस्ताक्षर किए थे। इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू कांग ने टैरिफ को लेकर अमेरिकी प्रशासन पर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यापारिक युद्ध से किसी का भला नहीं होता। बकौल कांग, हम इस अनुचित वृद्धि का कड़ा विरोध करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका को अपनी समस्याओं पर गौर करना चाहिए। ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए जो उसके लिए और पूरे विश्व के लिए फायदेमंद हो। हालांकि, ट्रंप ने अगले कुछ दिन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत करने की योजना बनाई है। जबकि उनके द्वारा चीन पर लगाया गया 10 प्रतिशत टैरिफ गत मंगलवार से ही लागू हो गया।

उधर, इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने भी मेक्सिको की चीजों पर 27 प्रतिशत टैरिफ लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इक्वाडोर के उत्पादकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में नोबोआ ने कहा कि वह मेक्सिको के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, लेकिन दुर्व्यवहार होने पर नहीं। हालांकि उन्होंने विस्तार से इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। राष्ट्रपति नोबोआ ने सिर्फ इतना कहा है कि जब तक मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए नहीं होता, मेक्सिको की चीजों पर 27 फीसदी टैरिफ लागू होगा।

वहीं, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रुडो और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ अलग-अलग बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों पर टैरिफ लगाए जाने के फैसले को लागू करने पर कम से कम एक महीने के लिए रोक लगाने पर सहमति जताई है। बता दें कि टैरिफ लगाए जाने के बाद, कनाडा के पीएम टुडो ने कहा था कि अमेरिका की कार्रवाई ने हमें एकजुट करने के बजाय अलग थलग कर दिया है। उन्होंने कहा था कि उनका देश शराब और फलों सहित 155 अरब डॉलर तक के अमेरिकी आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। टुडो ने %एक्स% पर पोस्ट अपने हालिया बयान में कहा है कि, ट्रंप के साथ बातचीत में उन्होंने सीमा सुरक्षा पर अतिरिक्त सहयोग का वादा किया। इसके तहत टैरिफ को कम से कम 30 दिन के लिए रोक दिया जाएगा और हम साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वह भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई रोक रहे हैं।

वहीं, मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा कि ट्रंप ने मेक्सिको पर लगाए गए टैरिफ को एक महीने के लिए रोक दिया है। शिनबाम ने %एक्स% पर पोस्ट किया, %मेक्सिको तुरंत नैशनल गार्ड के 10,000 सदस्यों की तैनाती के साथ उत्तरी सीमा को मजबूत करेगा, ताकि मेक्सिको से अमेरिका में फेंटेनाइल सहित मादक पदार्थों की तस्करी को रोका जा सके।% वहीं, अमेरिका भी मेक्सिको में हथियारों की तस्करी रोकने के लिए तैयार है।

इसलिए सवाल यह भी है कि अमेरिका-चीन में पुनः शुरू हुए व्यापार युद्ध का कारोबारी लाभ आखिर कैसे उठाएगा भारत? उसे इस हेतु पुनः व्यापक तैयारी करनी होगी। खुद को दुनियावी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना होगा। ताकि चीन की तरह ही भारत पर भी दुनियावी देशों का भरोसा बढ़ सके। भारत को सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि कनाडा, मेक्सिको और चीन को भी निर्यात बढ़ाने हेतु पहल करनी चाहिए। पीएम मोदी का %मेक इन इंडिया, मेक फ़ॉर द वर्ल्ड% अभियान, उनकी इसी दूरदर्शिता की ओर इशारा भी करता है। इस नजरिए से भारतीय मानव संसाधनों और आधारभूत संरचनाओं में भी वो लगातार निवेश कर-करवा रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि भारत समकालीन वैश्विक परिस्थितियों का भरपूर कारोबारी फायदा अपनी जनसंख्या के भरणपोषण और राष्ट्र को एक नई मजबूती प्रदान करने के लिए उठाएगा।

मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा और पूर्व गृह मंत्री की डायरी

जूलियो रिबैरो

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा लिखी गई एक किताब पाकर मैं वाकई हैरान रह गया, जिसके बारे में मैंने सुना था कि कैसे पद पर रहते हुए पुलिस कर्मियों के तबादले राजनीतिक दबाव में किए जाते थे। उन्हें एक आई.पी.एस. अधिकारी से कड़ी टक्कर मिली, जिसकी प्रतिष्ठा भी उनसे मेल खाती थी।

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), एन.सी.पी. (शरद पवार गुट) और कांग्रेस पार्टी की महा विकास अघाड़ी (एम.वी.ए.) सरकार ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर के तौर पर गलत आदमी को बिठाया था। साथ ही, शरद पवार ने 'गृह मंत्री की डायरी' के इस लेखक को पुलिस बल के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले मंत्री के तौर पर मनोनीत किया था! यह एक ऐसा घातक संयोजन था, जो जल्द ही फटने वाला था। और फटा भी।

25 फरवरी, 2021 को, शहर के एक पॉश रिहायशी इलाके अल्टामाऊंट रोड पर मुकेश अंबानी के घर 'एंटीलिया' के बाहर 20 जिलेटिन छड़ों से लदी, लेकिन सौभाग्य से बिना डेटोनेटर वाली एक स्कॉर्पियो कार खड़ी पाई गई। कार का पता मनसुख हिरेन नामक व्यक्ति से लगाया गया, जो पुलिस कमिश्नर के खासमखास, 'एनकाऊंटर स्पैशलिस्ट' सचिन वाजे का दोस्त है, जो क्राइम ब्रांच में असिस्टैंट पुलिस इंस्पैक्टर (ए.पी.आई.) के तौर पर काम करता है। राज्य पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (ए.टी.एस.) और केंद्र सरकार की राष्ट्रीय जांच एजैंसी (एन.आई.ए.) द्वारा यह स्थापित किया गया था कि ए.पी.आई. वाजे को पहले भी कई बार उसी स्कॉर्पियो कार में घूमते देखा गया था।स्पष्ट था कि वाजे की अगुवाई में सिटी पुलिस की क्राइम ब्रांच की खुफिया इकाई अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो लगाने में शामिल थी, जिसके कारण आज तक स्पष्ट नहीं

हो पाए हैं।

सचिन वाजे को हत्या के आरोप में 16 साल के लिए ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने खुद को 'एनकाऊंटर स्पैशलिस्ट' के रूप में पेश करते हुए विजिटिंग कार्ड छपवाए थे और निजी सुरक्षा व्यवसाय में उनके सहयोगी संभावित ग्राहकों को ऐसे विजिटिंग कार्ड वितरित करते थे। वाजे ने पुलिस में अपनी सेवा के शुरुआती वर्षों में इंस्पैक्टर प्रदीप शर्मा के अधीन काम किया था, जिन्हें 'एनकाऊंटर स्पैशलिस्ट' के रूप में जाना जाता है। शर्मा और वाजे एक-दूसरे के संपर्क में थे और साथ ही उस आई.पी.एस. अधिकारी के भी, जिसे अनिल देशमुख ने अपनी किताब में निशाना बनाया है। आई.पी.एस. अधिकारी को एम.वी.ए. सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसके गृह मंत्री अनिल देशमुख थे (और उस हैसियत से मुंबई के पुलिस आयुक्त के चयन पर उनसे सलाह ली जानी तय थी)। इससे पहले वह पड़ोसी शहर ठाणे के पुलिस कमिश्नर रह चुके थे। ठाणे के निवासियों की नजर में उनकी छवि बहुत खराब थी। अपने ही लोगों की नजर में उनकी छवि और भी खराब थी, जिनका नेतृत्व करने के लिए उन्हें चुना गया था।

मंत्री की जांच के दायरे में आए आई.पी.एस. अधिकारी ने ठाणे कमिश्नर के रूप में अपनी नियुक्ति समाप्त होने के बाद मुंबई पुलिस प्रमुख के पद के लिए बहुत प्रयास किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा हाईकमान ने इस पर असहमति जताई थी, जिसने मुंबई के पुलिस प्रमुख के रूप में गलत व्यक्ति को स्थापित करने के जोखिम का सही आकलन किया था। नियुक्त व्यक्ति शरद पवार की तीखी निगाहों से कैसे बच गया? अधिकारी ने खुद यह बताया कि शरद पवार ने उसका साक्षात्कार लिया था और उसे सलाह दी थी कि वह एक बहुत सम्मानित बल को निराश न करे और उसका अच्छा नाम खराब न करे। एंटीलिया कांड के बाद पुलिस आयुक्त के साथ अपने संबंधों के बारे में अनिल देशमुख का विवरण, उनके मित्र से दुश्मन बने व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोपों पर सी.बी.आई. और फिर एन.आई.ए. द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में खुद का बचाव है, जब उन्हें पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया गया था।

मंत्री पर सी.पी. ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने (सी.पी. के) दाहिने हाथ सचिन वाजे को बुलाया था और उनसे सौ करोड़ रुपए प्रति माह की मांग की थी, जो कि वाजे द्वारा बार मालिकों और अन्य लोगों से की जा रही अवैध वसूली का हिस्सा था। पूर्व गृह मंत्री ने अपनी प्रकाशित पुस्तक में यह नहीं बताया कि आयुक्त को क्यों और कैसे चुना गया। उन्हें इस सवाल का जवाब देना चाहिए क्योंकि प्रदर्शन में गिरावट वहीं से शुरू हुई। इसके अलावा वह यह भी नहीं बताते कि गृह मंत्री के रूप में उन्होंने सचिन वाजे पर हत्या के आरोप के बावजूद उनकी सेवा में बहाली पर आपत्ति क्यों नहीं जताई। इंटैलिजैंस यूनिट का नेतृत्व एक सीनियर इंस्पैक्टर को करना चाहिए। एक ए.पी.आई. को उस महत्वपूर्ण यूनिट का प्रमुख कैसे बनाया गया? सी.पी. ने सोशल सर्विसिज यूनिट के प्रभारी असिस्टैंट सी.पी. को क्यों बुलाया और उन्हें वाजे को अपने काम में शामिल करने के लिए क्यों कहा?

अंबानी के घर के बाहर एक कार में विस्फोटकों की खोज अपने आप में एक संकेत थी कि शहर के पुलिस प्रशासन में चीजें गलत हो रही थीं। कोई ए.पी.आई., यहां तक कि सचिन वाजे जैसा एक दबंग भी, अपने कमिश्नर की जानकारी के बिना इस तरह की परियोजना को अंजाम देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर कमिश्नर इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें योजना के बारे में कुछ नहीं पता था तो यह स्वीकारोक्ति ही उन्हें उच्च पद पर रहने के लिए अयोग्य ठहराएगी। इसके बाद स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की कथित तौर पर एनकाऊंटर विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा की गई हत्या ने यह साबित कर दिया कि एनकाऊंटर विशेषज्ञों की अवधारणा को हमेशा के लिए दफना दिया जाना चाहिए। वह दफनाने का काम कई साल पहले एक पूर्व आयुक्त अनामी रॉय ने किया था। शहर के नागरिक तब तक राहत की सांस ले रहे थे, जब तक कि सी.पी. ने सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच में शामिल नहीं कर लिया और उन्हें ऐसे अधिकार नहीं दे दिए, जो उनके पद से कहीं ज्यादा थे। क्या मंत्री को शहर की पुलिस में चल रही हलचल के बारे में पता नहीं था क्योंकि वाजे आयुक्त के दूसरे व्यक्तित्व के रूप में काम कर रहे थे?

स्कॉर्पियो कांड के बाद आयुक्त एम.वी.ए. सरकार को गिराने के लिए उस समय विपक्ष में रही बी.जे.पी. के साथ मिलकर काम करके अपनी गलती से बच निकला। यह एक बहुत ही संदिग्ध सौदा था जिसने राजनेताओं और इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाया।और यही बात मुंबई के नागरिकों को ड्क्षचतित कर सकती है। अनिल देशमुख ने इस घटना में अपनी भूमिका का जो बचाव किया है, जैसा कि उनकी किताब में दर्शाया गया है, वह वैसा ही है, जैसा कि उन्होंने अपने बचाव में कहा था। उन्होंने किताब में सी.पी. के खिलाफ जो तथ्य उजागर किए हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन कानून की अदालत में।

अवैध प्रवासन के मानवीय हल के लिए विशेष नीति की जरूरत

शोभना जैन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आदेश स्वरूप अमेरिका द्वारा अवैध भारतीय प्रवासियों को स्वदेश वापस भेजे गए ऐसे प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था भारत तो आ गया है, लेकिन जिस तरह से इन भारतीयों को एक सैन्य विमान में भरकर अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया उससे प्रतिपक्ष सहित समाज के एक बड़े वर्ग ने रोष जताया है। उनका कहना है कि जिस तरह से इन भारतीयों को, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, 'बंदियों' की तरह से सैन्य विमान में भर कर भारत भेजा गया, वह निहायत ही अमानवीय तरीका है। दरअसल यह कार्रवाई ट्रम्प के उस चुनावी वादे के संदर्भ में की गई है, जिसमें उन्होंने गैरकानूनी ढंग से अमेरिका में एक करोड़ से अधिक अवैध प्रवासियों के रहने के दावे किए थे और उन्हें वापस उनके देश भेजे जाने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया था ताकि अमेरिकियों को अपने देश में रोजगार मिल सके। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करते ही गत 20 जनवरी के बाद उन्होंने इसे अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया। हालांकि अमेरिका में मौजूद अवैध प्रवासियों में भारत की हिस्सेदारी बमुश्किल तीन प्रतिशत बताई जाती है और इसकी तुलना में अमेरिका के पड़ोसी देश, मैक्सिको या लातिन अमेरिका से बड़ी संख्या में लोग गैरकानूनी रूप से अमेरिका जाते हैं। अमेरिका ने इस श्रेणी में 18000 भारतीयों को चिन्हित किया है, जिसके तहत 100 से अधिक भारतीयों का पहला जत्था कल भारत पहुंचा। हालांकि अपुष्ट आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में लगभग 7.25 लाख भारतीय अवैध तरीके से रहते हैं। इनमें बड़ी तादाद में वहां कार्यरत आईटी प्रोफेशनल शामिल हैं जिनका कहना है कि वर्क वीजा समाप्त जरूर हुआ लेकिन वे उसके नवीकरण का प्रयास कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसे भारतीयों का अमेरिका के आर्थिक तकनीकी विकास में खासा योगदान है, जिसके चलते वहां अनेक राज्यों और प्रबुद्ध वर्गों ने ट्रम्प के इस फैसले का विरोध भी किया है। यह सही है कि किसी भी देश को पूरी जांच के बाद दस्तावेज अपुष्ट पाए जाने पर अवैध प्रवासियों को स्वदेश भेजने का अधिकार है लेकिन यह वापसी मानवीय ढंग से होनी चाहिए। अवैध आव्रजन पर रोक लगाने पर भारत का रवैया भी स्पष्ट है, क्योंकि अवैध प्रवासन भारत में भी एक गंभीर मसला है और भारत का मानना है कि इससे संगठित अपराध को मदद मिलती है। यही कारण है कि साल 2023 में जब अवैध प्रवासन का मसला राज्यसभा में उठा, तब यह कहा गया कि कई देश अपने यहां मौजूद अवैध प्रवासी भारतीयों की संख्या तब तक नहीं बताते, जब तक कि उनको निर्वासित नहीं किया जाता, लेकिन इसकी जानकारी भी दी गई कि देश में 30 अक्तूबर, 2023 तक 2,925 ऐसे एजेंटों की पहचान कर ली गई थी, जो गलत तरीके से भारतीयों को विदेश भेजते हैं। अगले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका यात्रा पर जाएंगे जहा ट्रम्प से मुलाकात के दौरान प्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। पीएम की यात्रा से ठीक पहले ट्रम्प प्रशासन द्वारा इस कदम की शुरुआत करना, वो भी उन्हें सैन्य विमान से अमानवीय तरीके से भारत वापस भेजा जाना सवालों के घेरे में तो है ही, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मसले पर दोनों देशों के बीच आपसी सहमति से मुद्दे को हल कर लिया जाएगा।

आयकर में राहत, किसानों को उम्मीदें, लेकिन क्या यह बजट सबको खुश कर पाया?

मोहन सिंह

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में अपने घोषित लक्ष्य के मुताबिक ही किसानों, दलित महिलाओं और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ मदद की घोषणा की है। इस बजट में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया है। अब छोटे कारोबारियों को भी 5 लाख तक के क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। महिलाओं को उद्यमशील बनाने के लिए 5 लाख तक के कर्ज की सुविधा घोषणा इस बजट में किया गया है।

दरअसल, कृषि मंत्रालय से अलग मत्स्य पालन विभाग बनाने के बाद अब मछुआरों के लिए स्पेशल इकॉनॉमिक जोन बनाने की भी घोषणा इस बजट में किया गया है। एमएसएमई सेक्टर की कर्ज की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। इन घोषणाओं का उद्देश्य कृषि , छोटे उद्योगों, और मछुआरों को अपनी उद्यमशीलता बढ़ाने के साथ - साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन करना भी है।

भारत को छोटे खिलौना उद्योग का हब बनाने की घोषणा किया गया है। इस घोषणा से बनारस के लकड़ी के खिलौना बनाने वाले छोटे उद्यमियों के मुरझाए चेहरे खिल जाएंगे। चमड़ा उद्योग में सरकार ने निवेश बढ़ाने की घोषणा किया है। सरकार को उम्मीद है कि इस सेक्टर में 22 लाख नौकरियों के सृजन की संभावना है।

मोदी सरकार ने पहली बार राज्य खनन सूचकांक बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य खनन क्षेत्र के प्रदर्शन और भविष्य की तैयारी मापने के लिए प्रमुख खनिजों और लघु खनिजों के सम्बन्ध में राज्यों के राज्यों के खनन क्षेत्र के प्रदर्शन दर आकलन करना है। इस पहल के तहत खान मंत्रालय ने आई आई टीआई आईएसएम धनबाद के साथ मिलकर एक कार्यशाला में राज्यों के खनन क्षेत्र के प्रदर्शन पर चर्चा किया गया है।

मोदी सरकार के इस बजट में बिहार में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं किया गया है। इनमें पटना एयरपोर्ट का विस्तार, पश्चिमी कोशी नहर को वित्तीय मदद भी शामिल है।

पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के वित्तीय मदद से उम्मीद है कि लगभग 50 हजार एकड़ कृषि जमीन की सिंचाई संभव हो सकती है। इसके अलावा बिहार में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का भी बजट में ऐलान किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ेगी। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के अपने पुराने संकल्प को इस साल के बजट में फिर दुहराया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे कम निवेश से स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा।

इस बाबत सरकार की पचास हजार पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने की योजना है। बजट में महात्मा बुद्ध

के जन्मभूमि समेत बुद्ध से जुड़े ऐसे 52 पर्यटन स्थलों को भी विकसित करने की घोषणा की गई है। बताते चलें कि बिहार में महात्मा बुद्ध से जुड़े अधिकतर ऐतिहासिक स्थल हैं। इसका मकसद भी है स्थानीय स्तर रोजगार को बढ़ावा देना है। बिहार में एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने के साथ ही बिहटा हवाई अड्डे को ब्राउन फील्ड एयर पोर्ट के रुप में विकसित करने की घोषणा भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है।

बिहार के लिए एक और पैकज की घोषणा इस बजट में की गई है। वह है बिहार मखाना बोर्ड की स्थापना। यह प्रयास किसी सरकार की ओर से पहली बार हुआ है। इससे अब तक उपेक्षित पड़े मखाना किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण जगी है। इससे मखाना को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध हो जाएगा। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में मखाने की बड़े पैमाने पर खेती होती है। इसका मकसद भी स्थानीय स्तर पर बिना किसी ख़ास निवेश के रोजगार का सृजन करना ही है। बिहार के लिए इन तमाम घोषणाओं की वजह से विपक्ष मोदी सरकार के इस बजट को पूरे देश की बजाय बिहार का बजट बता रहे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों में होने वाले अनुसंधानों और नवाचारों को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश में आईआईटी संख्या की बढ़ाने की भी घोषणा की है। शहरी विकास के लिए एक लाख करोड़ का इंतजाम किया गया है। साथ ही केवाईसी की प्रक्रिया को भी आसान बनाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है।

हर बजट से देश के मध्यवर्ग को और खासकर नौकरी पेशा वाले वर्ग को कुछ खास उम्मीदें होती हैं। बहुत हद तक मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में मध्य वर्ग के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। पहली बार 12 लाख की आय को आयकर सीमा से मुक्त किया गया है। इस एक छूट से 12 लाख की आमदनी पर मिली राहत से 12 लाख के सालाना आमदनी पर 80 हजार रुपए 18 लाख की आमदनी पर 90 और जिनकी आमदनी 25 लाख से ज्यादा होगी उन्हें 1 लाख 10 हजार रुपए का मुनाफा होगा।

सरकार की इस घोषणा को भी विपक्ष चार दिनों बाद दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों के नफा - नुकसान चश्में से ही देख रहे हैं। ऊपरी स्तर पर यह बजट सब को कुछ न कुछ खास देते हुए लग रहा है। यह बजट मोदी सरकार के उस मंशा के अनुकूल ही कहा जा सकता है कि आम जनता इस सरकार से किसी तरह के मुफ्त स्कीम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

सरकार का काम है मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना नहीं , ऐसी सुविधाओं का निर्माण करना है, ताकि आमजन अपनी मेहनत, कौशल और हुनर से अपने विकास के लिए नये क्षितिज का आविष्कार करे और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करें। बढ़ती मंहगाई और किसानों की घटती आमदनी को ध्यान में रखते हुए इस बजट में किसानों को सरकार से उम्मीद थी कि किसान सम्मान निधि में शायद इस बजट में वृद्धि हों, जो नहीं हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर कच्चे तेल का भाव लगातार कम हो रहा है। पर उस लिहाज से डीजल -पेट्रोल के कीमत में कोई कमी नहीं की गई। हालांकि, इसकी काफी गुंजाइश थी। देश की जियो और बीपी जैसी निजी कंपनियां डीजल और पेट्रोल पर कच्चे तेल के भावों में आई कमी का फ़ायदा अपने उपभोक्ताओं को दे भी रहे हैं। अगर ऐसा होता, तो किसानों और छोटे - बड़े उद्योगों के लिए यह बड़ी राहत की बात होती। सरसरी निगाह से देखा जाए तो इस बजट को संतुलित बजट कहा जा सकता है। जिसमें आमदनी चवन्नी खर्चा रुपैया के अतिरेक से बचने की कोशिश भी दिखाई देती है। इस साल के बजट में पिछले साल की तुलना में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को भी साधने की कोशिश दिखती है।

कितना सही है नाश्ते में दही लेना

नाश्ते में हम सभी कुछ ऐसा खाना पसंद करते हैं, जो खाने में टेस्टी हो और हमारे शरीर को पूरा दिन काम करने की एनर्जी देता रहे। ऐसे में ज्यादातर लोग किसी ना किसी रूप में नाश्ते में दही खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या नाश्ते में दही लेना एक स्वस्थ विकल्प है?

पाचक होती है लेकिन नींद दिलाती है

- यदि आपके दिन शुरुआत ही दही के साथ हो रही है तो यह आपको एनर्जी देने के स्थान पर नींद दिला सकती है और शरीर में सुस्ती बढ़ा सकती है। इसलिए दही कभी भी आपके फर्स्ट फूड का भाग नहीं होना चाहिए। हालांकि दही नाश्ते का एक शानदार हिस्सा है। यदि आप इसे खाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं तब.

समझे विरोधी बातों का अर्थ

- एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि दही नाश्ते में खाना अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि इसे खाने से सुस्ती बढ़ सकती है। दरअसल, ये दोनों ही बातें सही हैं। दही खाने पर आपको एनर्जी मिलेगी या सुस्ती आएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दही खाने का आपका तरीका क्या है।

इस तरह खाएं और इस तरह ना खाएं दही

- आप नाश्ते में चपाती, पराठा, चिल्ला आदि के साथ दही खा सकते हैं। एक कटोरी दही का सेवन नाश्ते में करना शरीर के लाभकारी होता है और पाचनतंत्र को सही करता है। साथ ही शरीर को दिनभर के लिए ऊर्जा देने में लाभकारी होता है।
- लेकिन नाश्ते में दही का सेवन तभी करना चाहिए जब आप सुबह के समय नाश्ते से पहले कुछ खा या पी चुके हों। जैसे, सुबह की शुरुआत आपने पानी के साथ की हो और फिर चाय-टोस्ट, स्प्राउट्स या ड्राईफ्रूट्स आदि खाए हों। इसके एक घंटे बाद यदि आप नाश्ते में दही का सेवन करते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। आपको गैस बनने की समस्या है तो इन 5 सब्जियों से बचना चाहिए

खाली पेट नहीं खानी चाहिए दही

- सुबह के समय आप नाश्ते में केवल मीठी दही का उपयोग कर सकते हैं। खट्टी दही खाने से परहेज करें। साथ ही नाश्ते में दही खाते समय आप इसमें एक चम्मच शक्कर मिला सकते हैं। यदि आपको शुगर की समस्या नहीं है तब।
- दिन की शुरुआत यदि किसी भी कारण देरी से हुई हो और आपके पास नाश्ता करने का समय ना हो तो भूलकर भी खाली दही ना खाएं। यदि आप खाली पेट दही खाते हैं तो आपको जबदस्त नींद आएगी और आप खुद को बहुत थका हुआ अनुभव करेंगे।
- ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाली पेट दही खाने से कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर कम होने की समस्या हो जाती है। इससे शरीर में ब्लड का फ्लो कम होता है और ऑक्सीजन का स्तर घटने लगता है। यही कारण है कि बहुत तेज नींद आती है और बेहोशी जैसा अनुभव होता है।

आप चाहे मानसिक काम अधिक करते हैं या शारीरिक काम। यदि आपको काम करते समय बहुत जल्दी थकान होने लगती है तो इसका एक अर्थ यह होता है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या है। जी हां, केवल पोषण की कमी के कारण ही नहीं बल्कि शरीर में पानी की कमी के कारण भी जल्दी थकान होती है। जो लोग नियमित रूप से जरूरी पानी नहीं पीते हैं, उन्हें काम करते समय अधिक थकान होना और अन्य लोगों की तुलना में जल्दी थकान होने जैसी समस्याएं होती हैं। जानें, जल्दी थकान होने के अन्य कारण और उनके निवारण के तरीके

लगातार बनी रहती है थकान तो ऐसे रखें अपना ध्यान

जल्दी थकने की वजह

- आमतौर पर जो लोग बहुत जल्दी थकान होने की समस्या से पीड़ित होते हैं, उनके शरीर में कुछ खास तत्वों की कमी देखने को मिलती है.
- पानी की कमी
- खून की कमी
- विटमिन-बी 12 की कमी
- फोलेट या फॉलिक एसिड की कमी देखने को मिलती है।

जल्दी थकान से बचने के तरीकों में ना केवल अपने खान-पान पर ध्यान देना है बल्कि यह भी ध्यान देना है कि जिस डायट का सेवन आप कर रहे हैं और जिन ड्रिंक्स को आप ले रहे हैं, क्या वे आपके शरीर की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। यहां जानें कैसे रखा जाएगा इस बात का ध्यान.

तरल पदार्थों का सेवन

- जल्दी-जल्दी होने वाली थकान की समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि आप तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा दें। इनमें जूस, सूप, छांछ, दाल इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही समय-समय सादा पानी पीते रहें। वयस्कों को हर दिन कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए।

तनाव को नियंत्रित करना सीखें

- जल्दी थकने की एक बड़ी वजह लगातार बना रहनेवाला तनाव भी होता है। तनाव का कारण चाहे जो भी लेकिन यह व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से जल्द थका देता है। इसलिए तनाव से बचने के लिए हर दिन कुछ समय के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान जरूर करें। यह आपको मानसिक रूप से फिट रखने का काम करेगा।

फलियों का सेवन करें

- हरी फलियां कई तरह की वरायटी में आती हैं। खास बात यह है कि मौसम की प्रकृति और उस दौरान शरीर की जरूरत के अनुसार हर सीजन में आनेवाली फलियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं।
- हरी फलियां फाइबर युक्त होती हैं और इनका पाचन धीमी गति से होता है। इसलिए ये शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने का काम करती हैं, जिससे शरीर पर थकान कम हावी होती है।

ड्राईफ्रूट्स

- ऐसा नहीं है कि ड्राईफ्रूट्स का सेवन केवल सर्दियों में ही करना चाहिए। बल्कि सीमित मात्रा में और दूध के साथ ड्राईफ्रूट्स का सेवन गर्मियों में भी हर दिन किया जा सकता है।
- क्योंकि ड्राईफ्रूट्स केवल हमारे शरीर को गर्माहट देने का ही काम नहीं करते हैं बल्कि पोषण देने का काम भी करते हैं। शरीर की कमजोरी को दूर करने में मीट भी अच्छी भूमिका निभाता है। लेकिन कोरोना संक्रमण के दौर में हम आपको मीट खाने की सलाह नहीं देना चाहते हैं। इस समय में आप थकान से बचने के लिए ड्राईफ्रूट्स यानी सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं।

शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण और कारण

शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना कई रोगों का कारण बनता है। ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर सबसे जल्दी और सबसे बुरा असर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। इस स्थिति में कोई भी वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर पर हावी हो सकता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण और कारण क्या होते हैं.

शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण

- शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से अर्थ है कि शरीर को अपनी नियमित क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन ना मिल पाना।
- जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो सबसे पहले व्यक्ति को थकान महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती या सांस फूलने लगता है। इसके बाद शरीर में रक्त के प्रवाह की गति धीमी हो जाती है। इससे थकान और घबराहट बढ़ जाती है।

हो सकती हैं ये बीमारियां

- यदि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाए तो ब्रेन डैमेज और हार्ट अटैक तक की स्थिति बन जाती है। शुगर के रोगियों में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उनकी शुगर अचानक बहुत अधिक बढ़ सकती है, जो कि एक जानलेवा स्थिति भी बन सकती है।
- ऑक्सीजन का स्तर अचानक से बहुत अधिक घट जाने पर शरीर में थायरॉइड हॉर्मोन का संतुलन गड़बड़ा जाता है। इस स्थिति में थायरॉइड का स्तर या तो बहुत अधिक बढ़ सकता है या बहुत अधिक घट सकता है।

शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण

- शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कई कारण होते हैं, जो व्यक्ति की लाइफस्टाइल पर निर्भर करते हैं। जो लोग बहुत अधिक आलस से भरपूर जीवनशैली जीते हैं यानी फिजिकल ऐक्टिविटी नहीं करते हैं, उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
- जो लोग बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं लेकिन उसके हिसाब से डायट नहीं लेते हैं, उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है।
- जिन लोगों के भोजन में आयरन की मात्रा कम होती है अगर वे लंबे समय तक इसी तरह का भोजन लेते रहें तो उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। क्योंकि फेफड़ों सहित पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करने में आयरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

चैन की नींद सोना है तो जरूर करें यह काम

अगर आप चाहते हैं कि रात में आपको सुकून की नींद आए, पैरों में कुलन और बेचैनी के कारण आपकी नींद में किसी तरह की बाधा ना आए तो आपको सोने से पहले एक खास काम करना होगा। यह काम आपके शरीर को राहत देने के साथ ही दिमाग को भी शांति देगा। आइए, जानते हैं कि आखिर क्या और कैसे करना है.

आपको क्या करना है?

- बिस्तर पर जाने से पहले आपको अपने पैर साफ पानी से धुलकर कॉटन के कपड़े से पोछकर साफ करने हैं। इसके बाद सरसों के तेल से अपने पैरों की मालिश करें। यह मालिश 2 से 3 मिनट की भी हो तो काफी है। यहां जानें इस तरह हर दिन मालिश करने से आपको किस तरह के लाभ होंगे.

पैर के तलुए में होते हैं सभी एक्युप्रेशर पॉइंट्स

- हमारे पैर के तलुओं में पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। पैर के तलुओं पर मसाज करने से इन पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है, जिससे शरीर का तनाव कम होता है और मानसिक शांति बढ़ती है। इसलिए आप अच्छी नींद आती है।

ताउम्र रहेंगे युवा

- अगर आप हर दिन सोने से पहले अपने पैर के तलुओं पर सरसों के तेल से मालिश करेंगे तो आप ताउम्र युवा बने रहेंगे। यहां युवा बने रहने से हमारा आशय है कि आपके दांत, आपकी दृष्टि और आपके शरीर के जोड़ों में किसी तरह का दर्द या समस्या नहीं हो पाएगी।

चश्मा नहीं लगेगा

- यदि आप सोने से पहले हर दिन अपने पैरों पर सरसों तेल से मालिश करते हैं तो आप अपनी कमजोर आइसाइट को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक या दो हफ्ते में ही इसका असर देखने को मिल जाएगा।

पाचन को ठीक रखे

- आपको जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है। लेकिन यह सही है कि जो लोग नियमित रूप से अपने पैर के तलुओं पर मालिश करते हैं या किसी और से कराते हैं, उनका पाचनतंत्र अन्य लोगों की तुलना में काफी ठीक रहता है। साथ ही उन्हें पेट संबंधी रोग नहीं घेरते हैं।
- साथ ही ऐसे लोगों के शरीर पर थकान हावी नहीं हो पाती है। पैर के तलुओं की मसाज करने से शरीर के डैमेज सेल यानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की जल्द मरम्मत होती है। इससे त्वचा भी चमकदार बनी रहती है। तो देर किस बात की, खूबसूरती और सेहत के लिए आज से ही शुरू करें पैर के तलुओं की मालिश।

ड्राई आई सिंड्रोम का संकेत हो सकता है आंखों में पानी आना

आंखे शरीर का सबसे जरूरी, सुंदर और नाजुक अंग है। सर्दी के मौसम में नमी और ठंडक के कारण आंखों में पानी आ जाता है लेकिन यह ड्राई आई सिंड्रोम का संकेत भी हो सकता है। इस बीमारी में आंखों से बहुत ज्यादा पानी आना, धुंधला दिखाई देना और चुभन महसूस होना, सूजन, रैशेज, लालपन जैसे लक्षण दिखाई देते है। इस बीमारी का समय पर इलाज न करने पर आंखों की रोशनी जा भी सकती है। ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप डॉक्टर की दवाइ के साथ-साथ कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। इन घरेलू नुस्खों की मदद से आप बिना किसी नुकसान के इस परेशानी से छुटकारा पा सकते है।

गीला कपड़ा - आंखों को हाथों से इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आंखों में जलन, दर्द या खुजली होने पर साफ पानी में कपड़े को भिगोकर आंखों की सफाई करें। इससे किसी भी तरह की बीमारी का खतरा कम हो जाता है।

नारियल का तेल - नारियल तेल में मौजूद गुण आखों की गंदगी को साफ करते हैं। रोजाना आंखों के नीचे और आस-पास नारियल के तेल की मालिश करें। आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगा।

हर्बल टी - कोमोमाइल या पेपरमिंट चाय की पत्तियों को थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दें। इसके बाद थोड़ी-थोड़ी देर में आंखों की सिकाई करें। ध्यान रहें कि पानी ज्यादा गर्म न हो।

नमक - कई बार आंखो में जलन और खुजली के कारण पानी आने लगता है। ऐसे में आप 1 गिलास गर्म पानी में चुटकीभर नमक डालकर आंखों की सिकांई करें। दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल खुजली और जलन की परेशानी को दूर कर देगा।

बेकिंग सोडा - साफ पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर गर्म करें। पानी थोड़ा रह जाने पर इससे अपनी आंखों को धो लें। इससे आपको आराम मिल जाएगा।

ठंडा दूध - कॉटन बॉल को ठंडे दूध में डिप करके अपनी आंखों के आस-पास रगड़ें। इसके अलावा आप कॉटन बॉल को ठंडे दूध में भिगोकर रख भी सकते है। इन उपायों को सुबह-शाम करने से आपको आराम मिल जाएगा।

एलोवेरा - एलोवेरा जेल में 1 चम्मच शहद और 1/2 कप एल्डरबैरी चाय मिलाएं। रोजाना दिन में 2 बार इस मिश्रण से अपनी आंखों को धोएं। आपकी परेशानी कुछ समय में ही दूर हो जाएगी।

कच्चा आलू - एस्ट्रिंजेंट के गुणों से भरपूर कच्चा आलू आंखों में पानी आने की समस्या से जल्दी राहत देता है। आलू की पतली स्लाइस काट कर कुछ देर फ्रिज में रखें। इसके बाद इस ठँडी स्लाइस को 15 से 20 मिनट के लिए आंखों के उपर रख लें। 2-3 दिन तक इसका इस्तेमाल आपकी इस समस्या को दूर कर देगा।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पेरिस में एआई समिट की सह-अध्यक्षता करेंगे मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी के तीसरे सप्ताह में फ्रांस का दौरा करेंगे। जहां वे 11 फरवरी को पेरिस में एआई समिट 2025 की सह-अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रम में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और चीनी उपप्रधानमंत्री कई अन्य लोग शिरकत करेंगे। वहीं राजनयिक सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी इस दौरान तमाम फ्रांसीसी कंपनियों को प्रमुख के साथ मुलाकात और बातचीत भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी 12 फरवरी को मार्सिले में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। एयरोस्पेस, इंजन और पनडुब्बियों के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच सफल वार्ता चल रही है। असैन्य परमाणु ऊर्जा और रिएक्टरों पर भी अग्रिम वार्ता चल रही है; पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान ठोस घोषणाओं की संभावना भी है। इसके अलावा पीएम मोदी दक्षिणी फ्रांस के शहर मार्सिले में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन भी करेंगे।

संसद भवन में प्रधानमंत्री से मिले बिहार एनडीए के 30 सांसद

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल-यूनाइटेड (जेडी (यू)) और अन्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सहयोगियों के नेताओं सहित बिहार के लगभग 30 संसद सदस्यों ने अपने राज्य के लिए हालिया बजट घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त करने के लिए आज संसद में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बैठक सांसदों के लिए एक साथ आने और बिहार के विकास के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता में प्रधान मंत्री के साथ एकजुटता दिखाने का एक अवसर था। सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में, बिहार के सांसदों ने प्रधान मंत्री मोदी को एक सुंदर ढंग से तैयार की गई पेंटिंग भेंट की। यह इशारा प्रधान मंत्री के सम्मान का एक पारंपरिक रूप था, जो बिहार में एनडीए गठबंधन के सांसदों के बीच एकता पर जोर देता है। पेंटिंग की प्रस्तुति के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ललन सिंह और चिराग पासवान जैसी प्रमुख हस्तियों की तस्वीरें भी ली गईं। सांसदों ने सरकार के बजटीय उपायों की गहरी सराहना की।

भारतीयों के निर्वासन पर राउत ने सरकार को घेरा

नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शुक्रवार को अमेरिका से भारतीय प्रवासियों के निर्वासन को लेकर केंद्र की आलोचना की और तर्क दिया कि अमेरिका के विमान को उड़ान भरने और वापस जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा में अधिक मुखर भूमिका निभानी चाहिए थी। इस मामले में संजय राउत ने कहा, हमारे लिए, वे अपराधी नहीं हैं। उनके पैरों और हाथों की बेड़ियां हटा दी जानी चाहिए थीं, यह कानून का उल्लंघन था, अमेरिका के विमान को उड़ान भरने और वापस जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। राउत ने तर्क दिया कि एक बार जब ये व्यक्ति भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गए, तो उनके साथ भारतीय कानूनों के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए था, न कि अपराधियों के रूप में। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार को अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए और अधिक कड़ा रुख अपनाना चाहिए था।

लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टली, 17 को होगी हियरिंग

नईदिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। इस मामले में दो पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति पर फैसला होना था। इससे पहले 30 जनवरी को मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने दोनों अधिकारियों पर केस चलाने की मंजूरी दी थी। इसमें एक पूर्व आईएएस अधिकारी आर के महाजन भी शामिल हैं। बता दें कि पूर्व आईएएस आर के महाजन लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे बोर्ड में कार्यरत थे। पिछली सुनवाई के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। अधिवक्ता मनु मिश्रा फिजिकली कोर्ट के अंदर मौजूद थे। उससे पहले 16 जनवरी को सुनवाई टाल दी गई थी। उस दिन कोर्ट ने एक रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति नहीं दी थी। बता दें कि इस लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार के पांच सदस्य आरोपी हैं।

शिंदे गुट का बड़ा दावा, उद्धव खेमे के 6 सांसद बदलेंगे पाला

मुंबई। महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी के छह सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इसकी चर्चा जोरों पर है। शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने कहा कि पूरा यूबीटी ख़त्म होने वाला है। महाराष्ट्र में यूबीटी के विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद, पदाधिकारी सभी पार्टी छोड़कर शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। अब संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अलावा कोई भी उनके साथ नहीं रहने वाला है। बीजेपी सांसद योगेंदर चंदोलिया ने कहा कि असली शिव सेना एकनाथ शिंदे की, बाला साहेब ठाकरे की शिव सेना है। उनके लोगों (शिवसेना यूबीटी) को लगा होगा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब के अरमानों पर पानी फेर दिया है। धन के लालच में उसने अपने पिता के धर्म को पाप में बदल दिया। अंत में, उद्धव ठाकरे अकेले पड़ जाएंगे और उनकी पार्टी के सभी सदस्य असली शिवसेना में शामिल हो जाएंगे।

15 करोड़ के ऑफर पर दिल्ली में जंग, भाजपा ने की शिकायत, एलजी ने दिए जांच के आदेश

केजरीवाल और संजय सिंह से होगी पूछताछ

नईदिल्ली। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा भाजपा के खिलाफ लगाए गए विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। भाजपा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने दावों की जांच के आदेश दिए। जवाब में, एसीबी टीम आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह और पार्टी नेता मुकेश अहलावत सहित आप नेताओं से पूछताछ करने के लिए तैयार है।

दिल्ली एलजी के प्रमुख सचिव ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को रिश्वत की पेशकश के आरोपों पर एसीबी जांच कराने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा। दिल्ली एलजी को बीजेपी की शिकायत के बाद एक जांच आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि आरोप झूठे और निराधार हैं और बीजेपी की छवि खराब करने और मतदान के समापन के तुरंत बाद दिल्ली में दहशत और अशांति की स्थिति पैदा करने के इरादे से लगाए गए हैं।

यह जांच केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों से शुरू हुई है, जिन्होंने भाजपा पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी के 16 उम्मीदवारों से भाजपा में शामिल होने पर 15-15 करोड़ रुपये और मंत्री पद की पेशकश की गई थी। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, केजरीवाल ने आरोप लगाया, पिछले दो घंटों में, हमारे 16 उम्मीदवारों को फोन आए कि अगर वे आप छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं तो उनमें से प्रत्येक को 15-15 करोड़ रुपये और मंत्री पद की पेशकश की जाएगी।

केजरीवाल की बैठक के बाद बोले गोपाल राय- 50 सीटें जीतेगी आप

दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी (आप) के सभी 70 उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के आवास पर एकत्र हुए। यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई जब लगभग साने एक्जिट पोल भाजपा के पक्ष में चुनावी परिणाम की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आप नेता गोपाल राय ने बताया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आज आप के सभी विधायकों की बैठक हुई जिसमें सभी उम्मीदवारों ने अपनी रिपोर्ट दी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक,क्क करीब 50 सीटें जीतेगी और 6-7 सीटों पर कांटे की टक्कर होगी। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का जनादेश दिया है।

गोपाल राय ने कहा कि जिस तरह से गली गालोच पार्टी एग्जिट पोल के जरिए माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि वे सरकार बनाएंगे लेकिन उनकी हताशा हकीकत बयां कर रही है। जिस तरह से हमारे उम्मीदवारों को भाजपा में शामिल होने के लिए फोन आ रहे हैं और उन्हें मंत्री पद का प्रलोभन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे एग्जिट पोल के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सभी उम्मीदवारों से कहा है कि,क्क सरकार बनाने जा रही है।

आप विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि भाजपा आप विधायकों और उम्मीदवारों को लुभाने की कोशिश कर रही है। हमने अरविंद केजरीवाल को आश्वासन दिया है कि हममें से कोई भी बहकावे में नहीं आएगा। हमने मजबूती से चुनाव लड़ा और कल आप बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि चुनाव के बाद वह सभी प्रत्याशियों से मिलकर उनका फीडबैक ले रहे हैं। कई लोगों के फोन आ चुके हैं।

आप विधायकों को भाजपा की ओर से फोन आने को लेकर आप सांसद संदीप पाठक ने कहा कि ये बात सत्य के आधार पर कही गयी है। हमारे कई नेताओं के फोन आए हैं। हमने उस फ़ोन नंबर का भी खुलासा कर दिया है जिससे कॉल आए थे। यह दुनिया जानती है कि भाजपा कैसे काम करती है। उन्होंने कहा कि यह उनके चुनाव प्रबंधन का एक हिस्सा है. मतदान के बाद लोग वोटों की गिनती पर ध्यान केंद्रित करते हैं लेकिन वे (भाजपा) यह सब करते हैं।% वे यह सब बहुत साहसपूर्वक करते हैं।

भाजपा ने आप के खिलाफ एसीबी में दर्ज कराई शिकायत

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए खरीद-फरोख्त के आरोपों के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने यह फैसला तब लिया जब आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पार्टी पर उनकी पार्टी के सदस्यों को रिश्वत देने और दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले पार्टी बदलने की अपील करने का आरोप लगाया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके 16 उम्मीदवारों को बीजेपी से फोन आए और प्रत्येक को 15 करोड़ रुपये की पेशकश की गई। इसके जवाब में भाजपा ने कहा कि महाठग साहब, आपकी मनोहर कहानी और ड्रामेबाज़ी से हर कोई वाक़िफ़ है और आरोप लगाने के बाद माँफी मांगना भी आपको बहुत पसंद है, वैसे भी आपकी ये स्क्रिप्ट अब पुरानी हो चुकी है। बस थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए, 8 फ़रवरी को दिल्ली से आप-दा हमेशा के लिए जाने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह अपना आरोप वापस लेकर भाजपा से माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहें।

महाराष्ट्र के मतदाताओं का डेटा उपलब्ध नहीं कराने का मतलब है कि कुछ गलत है: राहुल

पूछा- ये 39 लाख वोटर कौन हैं?

नईदिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बार-बार मांग के बावजूद निर्वाचन आयोग की ओर से महाराष्ट्र के मतदाताओं के डेटा उपलब्ध नहीं कराने से लगता है कि कुछ न कुछ गलत है। नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा में) ने शिवसेना (उबाठा) के नेता संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग को पारदर्शिता लानी चाहिए, महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों से जुड़ी पूरे राज्य की मतदाता सूची उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या यहां की वयस्क आबादी से ज्यादा है। राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, ''हम उस पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने महाराष्ट्र में पिछला चुनाव लड़ा था। हम भारत के लोगों के ध्यान में महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में सामने आई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लाना चाहते हैं।

हमारी टीम ने मतदाता सूची और मतदान पैटर्न का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और हम कुछ समय से इस पर काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमें कई अनियमितताएं मिलीं।'' उन्होंने कहा कि देश के लिए, विशेषकर युवा लोगों के लिए जो लोकतंत्र के पक्षधर हैं और उसमें विश्वास करते हैं, इन निष्कर्षों से अवगत होना और समझना आवश्यक है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि पिछले साल लोकसभा चुनाव और फिर पांच महीने बाद हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच की अवधि में राज्य में हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर की संख्या में मतदाता बढ़ गए।'' उनके अनुसार, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में पांच महीनों में 39 लाख मतदाता जुड़े, जबकि पिछले पांच वर्षों में 32 लाख मतदाता जुड़े थे।

उन्होंने सवाल किए कि ये मतदाता कहां से आए हैं और ये कौन हैं? राहुल गांधी ने कहा, ''हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के बार-बार मांग के बावजूद निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र में मतदाताओं का डेटा उपलब्ध नहीं करा रहा है। इससे पता चलता है कि कुछ गलत हुआ है।'' उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और इनमें अधिकतर मतदाता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के हैं।

राहुल गांधी के आरोपों पर देवेन्द्र फडणवीस का पलटवार

महाराष्ट्र चुनाव ने नतीजों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बड़ा आरोप लगाया है। अब इसी को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि राहुल गांधी कवर फायर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 8 फरवरी के दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद उनकी पार्टी दिल्ली में कहीं नहीं रहेगी और इसलिए उस दिन वह क्या बोलेंगे, कैसे नया नैरेटिव गढ़ेंगे, वह उसी के लिए अभ्यास कर रहे हैं। देवेन्द्र फडणवीस ने आगे कहा कि यदि राहुल गांधी आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे और झूठ से खुद को सांत्वना देते रहेंगे - तो उनकी पार्टी का पुनरुद्धार संभव नहीं है। राहुल गांधी को अपनी हार का आत्ममंथन करना चाहिए।

खेल
प्रमुख समाचार

विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे दूसरा वनडे?

नागपुर। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे खेलेंगे या नहीं ये इस समय का सबस बड़ा सवाल है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज 6 फरवरी को नागपुर में खेले गए पहले मुकाबले से हुआ। इस मुकाबले की शुरुआत में फैंस का दिल उस समय टूटा जब उन्हें पता चला कि, चोटिल होने की वजह से किंग कोहली मैच नहीं खेल रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस के दौरान बताया कि विराट कोहली के घुटने में दिक्कत है जिस वजह से वह मैच से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह नागपुर वनडे में श्रेयस अय्यर को खेलने का मौका मिला।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा वनडे 9 फरवरी को कटक में खेला जाना है। क्या इस मुकाबले से पहले विराट कोहली फिट हो पाएंगे। फैंस की जुबां पर यही सवाल है। इस सवाल का जवाब भारत के उपकप्तान शुभमन गिल ने देकर फैंस का दिन बना दिया है। उनका कहना है कि वारट कोहली की चोट को लेकर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है और कहा है कि स्टार बल्लेबाज कटक में दूसरे वनडे के लिए टीम में वापस आ जाएगा। गिल ने कहा कि, जब वह सुबह उठे तो उनके घुटने में सूजन थी। कल के अभ्यास सत्र तक वह ठीक थे। चिंता की कोई बात नहीं है। वह अगले मैच के लिए निश्चित रूप से फिट होंगे। विराट कोहली की जगह नागपुर वनडे में शुभमन गिल नंबर-3 पर उतरे थे और इस खिलाड़ी ने 87 रनों की शानदार पारी खेल टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। गिल को इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया। गिल ने नंबर-3 पर खेलने को लेकर कहा कि, मुझे लगता है कि मैं टेस्ट मैचों में तीसरे नंबर पर खेलता हूं इसलिए ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं था। लेकिन, निश्चित रूप से, स्थिति थोड़ी अलग है। अगर आप तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और शुरुआती विकेट गिर जाते हैं। आपको स्थिति के अनुसार खेलना होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 78 हजार के नीचे निफ्टी 23,560 पर बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार (7 फरवरी) को लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन गिरावट में बंद हुए। ब्याज दरों में पांच साल बाद कटौती का बाजार के सेंटीमेंट पर खास असर नहीं पड़ा। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुक्रवार को मामूली बढ़त के साथ 78,119 अंक पर खुला। हालांकि, कुछ देर बाद यह गिरावट में चला गया। कारोबार के दौरान यह 77,475 तक फिसल गया था। अंत में सेंसेक्स 197.97अंक या 0.25% की गिरावट लेकर 77,860 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 भी गिरावट में रहा। यह 43.40 अंक 0.18 फीसदी की गिरावट लेकर 23,560 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में आईटीसी का शेयर सबसे ज्यादा गिरावट में बंद हुए। तीसरी तिमाही के नतीजे उम्मीदों से कमजोर रहने के बाद कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है।

रिजर्व बैंक ने 5 साल बाद घटाया रेपो रेट

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया। केंद्रीय बैंक ने लगभग पांच साल बाद रेपो दर में कटौती की है। इससे पहले मई, 2020 में कोविड-19 महामारी के समय रेपो दर को 0.40 प्रतिशत घटाकर चार प्रतिशत किया गया था। फिर रूस-यूक्रेन युद्ध के जोखिमों से निपटने के लिए आरबीआई ने मई, 2022 में दरों में बढ़ोतरी करनी शुरू की थी और यह सिलसिला फरवरी, 2023 में जाकर रुका था। रेपो दर दो साल से 6.50 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है। आरबीआई के गवर्नर ने संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन की बैठक में लिए गये निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि छह सदस्यीय समिति ने आम सहमति से रेपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय किया है।

वित्तवर्ष 25-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% रहने का अनुमान

नईदिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट के 6.4 फीसदी पर रहने के अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में 8.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के बाद चली वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में नरम विस्तार हो सकता है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, आगे चलकर आने वाले साल में आर्थिक गतिविधियों में और सुधार की संभावना है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चालू वित्त वर्ष के लिए आखिरी और अपनी पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि रबी फसल की अच्छी संभावनाओं तथा औद्योगिक गतिविधियों में अपेक्षित सुधार से 2025-26 में आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा।

महिंद्रा एंड महिंद्रा का दिसंबर तिमाही में 19% बढ़ा मुनाफा

नईदिल्ली। स्कॉर्पियो और थार जैसी धाकड़ गाड़ियां बनाने वाली ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुक्रवार (7 फरवरी) को अपने दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया। महिंद्रा का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 2024-25 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 19 फीसदी बढ़कर 2964 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की इसी तिमाही में यह 2,489.73 करोड़ रुपये था। महिंद्रा का ऑपरेशंस से रेवेन्यू दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 20 फीसदी उछलकर 30,538 करोड़ रुपये हो गया। यह एक साल पहले की इसी अवधि में 25,736.73 करोड़ रुपये था। सितम्बर तिमाही में यह 28,919.34 करोड़ रुपये थी। वहीं, कंपनी की टोटल इनकम वित्त वर्ष 2024 -25 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 31,228.32 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 29,596.56 करोड़ रुपये थी।

घरेलू विकास ही बनेगा हमारा हथियार

अजय बग्गा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार के वित्तीय रोडमैप को रेखांकित किया है। इस बजट का एक मुख्य आकर्षण राजकोषीय अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता है। सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 फीसदी निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के 4.8 फीसदी से कम है। राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सकल उधारी 148.2 खरब रुपये और शुद्ध उधारी 115.4 खरब रुपये रहने का अनुमान है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य आर्थिक प्रोत्साहन की आवश्यकता को विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के साथ संतुलित करना है।

मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, बजट में कराधान में परिवर्तनकारी सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। शून्य व्यक्तिगत आयकर स्लैब को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है यानी अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को आयकर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जिससे वेतनभोगी व्यक्तियों को पर्याप्त राहत मिलेगी और उनकी डिस्पोजेबल आय (कर चुकाने के बाद बची आय) में वृद्धि होगी।

इसके अतिरिक्त, समुद्री उत्पादों और महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया है, और जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवा अधिक किफायती हो गई है। बजट में कृषि पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने के लिए पहल की गई है। उच्च उपज वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की गई है, साथ ही किसानों के लिए

सब्सिडी वाले ऋण की सीमा में वृद्धि की गई है।

इन उपायों का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत की है, जो निर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। स्टार्टअप और बुनियादी ढांचे के विकास को समर्थन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के नए योगदान के साथ एक नया कोष स्थापित किया गया है। इस पहल से नवाचार को बढ़ावा मिलने और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। बीमा बाजार में पैठ बढ़ाने के लिए बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी गई है। इस कदम से अधिक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को आकर्षित करने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उपभोक्ताओं को बीमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराने की उम्मीद है।

बजट में आर्थिक विकास में परिवहन और कनेक्टिविटी के महत्व को रेखांकित किया गया है। दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेहतर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, विभिन्न उद्योगों को आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के विकास की एक नई नीति पेश की गई है। सरकार गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की सहायता के उपायों के साथ समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रोजगार को बढ़ावा देने और छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए बढ़ी हुई ऋण गारंटी की घोषणा की गई है।

भारत के विनिर्माण उत्पादन का 36 फीसदी उत्पादन करने वाले एमएसएमई क्षेत्र को इन पहलों से काफी लाभ होगा। कुल मिलाकर, कहा जा सकता है कि केंद्रीय बजट-2025 घरेलू विकास को बढ़ावा देते हुए धीमी होती वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति प्रस्तुत करता है। राजकोषीय अनुशासन, कर सुधार, कृषि उत्पादकता, विनिर्माण प्रोत्साहन, वित्तीय क्षेत्र उदारीकरण और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करके सरकार का लक्ष्य एक लचीली और समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।

छत्तीसगढ़ आपकी स्मृतियों में रहेगा अंकित : सीएम साय

नक्सल उन्मूलन से स्मार्ट सिटी तक अधिकारियों ने जाना छत्तीसगढ़ के विकास का सफर

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित हुए अधिकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है और नैसर्गिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध जैव विविधता इसे खास पहचान देती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में नेशनल डिफेंस कॉलेज से आए 18 सैन्य और सिविल सर्विस के अधिकारियों के दल ने छत्तीसगढ़ भ्रमण उपरांत उनसे मुलाकात कर अपने अनुभवों को साझा करते हुए यह बातें कही। मुख्यमंत्री ने उत्सुकता के साथ सभी सैन्य अधिकारियों से उनके छत्तीसगढ़ भ्रमण को लेकर चर्चा की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी अधिकारियों का आत्मीय स्वागत करते हुए प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं, सांस्कृतिक धरोहर और विकास यात्रा पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी अद्वितीय है। प्रदेश का 44 प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित है, और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा हमारी धरोहर का अभिन्न अंग हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का सौंदर्य अनुपम है। आपने जो यात्रा की है, वह सिर्फ प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव नहीं, बल्कि एक जीवंत संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ सफर भी है। यह अनुभव सदैव आपकी स्मृतियों में अंकित रहेगा।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि नक्सल उन्मूलन की दिशा में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। हम न केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से बल्कि शिक्षा, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों के माध्यम से भी इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने औद्योगिक और शहरी विकास के साथ-साथ ग्रामीण एवं आदिवासी समुदायों के उत्थान पर भी समान रूप से ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता, नवाचार और उत्कृष्ट शासन प्रणाली का उदाहरण बने। आपका यह भ्रमण हमारे प्रयासों को एक राष्ट्रीय और वैश्विक दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करता है।

नेशनल डिफेंस कॉलेज के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने अपने प्रवास के दौरान आईआईएम रायपुर, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, ग्रीन फील्ड सिटी और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का अवलोकन किया। इसके अलावा उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से कानून व्यवस्था और नक्सल उन्मूलन अभियान के संबंध में चर्चा की। अधिकारियों ने सिरपुर, एजुकेशन सिटी दंतेवाड़ा, कांकेर वुड आर्ट सेंटर, जंगल वारफेयर कॉलेज, कोंडागांव के टाटामारी और शिल्पग्राम, बादल एकेडमी और चित्रकोट जलप्रपात का भ्रमण किया।

दल का नेतृत्व कर रहे एडमिरल संदीप सिंह संधु ने बताया कि नेशनल डिफेंस कॉलेज के द्वारा प्रति वर्ष एक वर्षीय कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें सेना, सिविल सेवा और अंतरराष्ट्रीय रक्षा अधिकारियों को रणनीतिक विषयों पर प्रशिक्षित किया जाता है। इस वर्ष 124 अधिकारी इस कोर्स में शामिल हैं, जिनमें 13 भारतीय और 5 अन्य देशों के अधिकारी छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक ढांचे को समझने के लिए भ्रमण पर आए है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पी. दयानंद और डॉ. बसवराजू एस उपस्थित रहे। नेशनल डिफेंस कॉलेज के अधिकारियों में ब्रिगेडियर अमितोज सिंह, संदीप कुमार मिश्रा, कोमोडोर कार्तिक मूर्ति, ब्रिगेडियर अनिरुद्ध सिंह कंवर, एयर कोमोडोर शेखर यादव, ब्रिगेडियर गुरप्रीत सिंह मान, ब्रिगेडियर रजनीश मोहन, कैप्टन एम. व्ही. ओरपे सहित लंका, मोरक्को, नाइजीरिया, नेपाल और यूएई के अधिकारी शामिल थे।

भ्रष्टाचारी महापौर के नाम पर वोट मांगने डर रही है कांग्रेसः मीनल चौबे

रायपुर। नगर निगम चुनाव अब अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है निगम चुनाव जीतने प्रत्याशी अब अपना पूरा दम खम लगा रहे हैं बकौल भारतीय जनता के नेताओं की माने तो रायपुर नगर निगम में भाजपा का परचम लहराने जा रहा है जनता का भरपूर समर्थन भाजपा प्रत्याशियों को मिल रहा है और भाजपा नेताओं का मानना है कि इस बार रायपुर नगर निगम महापौर ऐतिहासिक अंतर से जीतने जा रही है और मीनल चौबे रिकॉर्ड कायम करने जा रही है साथ ही साथ रायपुर नगर निगम में भाजपा पार्षद दल भी बहुमत के साथ बैठेगा भाजपा द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी नीतियों और योजनाओं का लाभ भाजपा प्रत्याशियों को जरूर मिलेगा और जनता भाजपा प्रत्याशियों को भर भर के आशीर्वाद भी दे रही है ।शुक्रवार भाजपा प्रत्याशी मीनल चौबे ने अपने दैनिक जनसंपर्क रैली की शुरुआत रायपुर दक्षिण विधानसभा अंतर्गत भगवती चरण शुक्ल वॉर्ड से की जहां उनकी जनसंपर्क प्रचार रैली में उनके साथ रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल , कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और दक्षिण विधानसभा के विधायक सुनील सोनी भी उपस्थित थे वॉर्ड भ्रमण करते हुए सभी नेताओं ने जनता से रायपुर नगर निगम में भाजपा के निशान कमल फूल के पक्ष में मतदान का आशीर्वाद मांगा। भाजपा महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने अपनी जनसंपर्क रैली के दौरान प्रमुख चौराहों और मोहल्लों पर नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया।

सीएम साय के भव्य रोड और सभाओं में लाखों लोगों हुए शामिलः सवन्नी

रायपुर। भूपेंद्र सवन्नी ने कहा कि भाजपा के सुशासन की प्रदेश में प्रचंड लहर चल रही है। इसका ही नतीजा रहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के जितने भी भव्य रोड शो हुए हैं, उनमें अपार जनसैलाब स्वफूर्त उमड़ा है। श्री सवन्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के संबोधन को सुनने और नगरी निकायों में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए प्रदेश की जनता ने संकल्प ले लिया है। भाजपा सभी नगरी निकायों में भारी जीत हासिल करेगी।

श्री सवन्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5 फरवरी को कोरबा में आम सभा और इसी दिन रायगढ़ में रोड शो किया, जहां नगर और ग्रामीण अंचल की जनता ने भारी भागीदारी निभाई। इसी तारत्मय में 6 फरवरी को श्री साय डोंगरगढ़ में आयोजित बौद्ध धर्म के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही राजनांदगांव जिले में तीन छोटी सभाएं की, लेकिन श्री साय को सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े थे। श्री सवन्नी बताया कि 7 फरवरी को चिरमिरी में आमसभा को हजारों की भीड़ को संबोधित किया, इसके बाद मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर और बिलासपुर जिले में भव्य रोड शो किया। उक्त रोड और कार्यक्रमों में लाखों की संख्या में जनता ने भागीदारी निभाई। इसका सबसे बड़ी वजह है कि इस प्रदेश की जनता ने ठाना है कि निकाय चुनाव में भी कमल खिलाकर भाजपा का सुशासन लाएंगे। श्री भूपेंद्र ने कहा के मा .विष्णु देव साय जी की सरकार ने जो किसानों को धान की अतिरिक्त राशि का 12 हजार करोड़ रूपया एक मुश्त देने की बात कही है व महतारी वंदन की भी राशि को समय से जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी उनका आभार और अभिनंदन करती है।-

रमन सिंह के नाम से डरती है कांग्रेसइसीलिए झूठे बयान देती हैः श्रीवास्तव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह द्वारा राजनांदगाँव में भाजपा महापौर प्रत्याशी के समर्थन में आहूत एक कार्यक्रम में शामिल होने पर

चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी को कांग्रेस नेताओं के दिमागी दीवालियापन का परिचायक बताया है। लगातार हार से हताश और बौखलाई कांग्रेस राजनीतिक मूर्खता की पराकाष्ठा कर रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष पद को संवैधानिक पद बताकर डॉ. सिंह के भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होने को संविधान का उल्लंघन बता रहे कांग्रेसियों में जरा भी शर्म बाकी नहीं रह गई है। मुद्दों के संकट से जूझ रही कांग्रेस हर बार खाली संविधान-संविधान की रट लगा रही है, जबकि वे न तो संविधान पढ़ते हैं, न संविधान को मानते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए चरणदास महंत के कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने पर कांग्रेसियों ने तब मुँह में दही जमा रखा था।

कांग्रेस की विश्वनीयता पूरी तरह समाप्तः देवलाल ठाकुर

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते समय बैज ने घोषणा पत्र में 36 वादे होने की बात कही थी जबकि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सिर्फ 34 वादे ही किए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि यह बड़े ही हैरत की बात है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष घोषणा पत्र की लॉन्चिंग कर रहे थे और उन्हें यह नहीं पता था कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कितने वादे किए हैं?

श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र किसी आम आदमी ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया था। इससे यह साफ पता चलता है कि अपने घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस कतई गंभीर नहीं है। कांग्रेस के लोगों को यह पता ही नहीं है कि अपने घोषणा पत्र में वे क्या वादे कर रहे हैं? कितने वादे कर रहे हैं? घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र हमेशा ऐसा ही रहा है। 2018 में सर- सर बोलने का विश्व रिकॉर्ड कायम करके कांग्रेस के नेताओं ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसका क्या हश्र हुआ, पूरा प्रदेश जानता है। उसमें भी 36 वादे थे जिसमें से कितने वादे पूरे हुए, इसे लेकर भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव समेत तमाम नेता-मंत्री अलग-अलग दावे करते रहे लेकिन वादे एक भी पूरे नहीं किए। श्री ठाकुर ने कहा कि 2019 में निकाय चुनाव में भी कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर आई लेकिन वह भी झूठ का पुलिंदा ही साबित हुआ और कांग्रेस की सरपरस्ती में निकायों पर काबिज कांग्रेस के लोगों ने निकायों को लूट, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार और कुशासन का अड्डा बनाकर रख दिया था।

चुनाव में हार के डर से भाजपा शराब, पैसा बांटने में लगी

रायपुर। बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र शर्मा ने कहा कि भाजपा सत्ता और भ्रष्टाचार के पैसे का दुरुपयोग करके चुनाव प्रभावित करने में लगी है। बेमेतरा-सिमगा मार्ग में पकड़ाई शराब भी चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से भाजपा ने मंगाया था। सत्ता में बैठी हुई भाजपा को पता चल चुका है कि प्रदेश में उसकी सरकार के खिलाफ वातावरण है जनता भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करेगी। 1 साल में साय सरकार जनता में अलोकप्रिय हो चुकी है। चुनाव में संभावित हार से घबराकर भाजपा शराब पैसा वितरित कर रही है। बिना सरकार के संरक्षण के राज्य की राजधानी के समीप सिमगा तक 700 पेटी शराब से भरा कंटेनर दूसरे राज्य तक कैसे पहुंच गया। चुनाव आयोग राज्य सरकार से पूछताछ करे।प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने जनता से जो वादा किया था, एक साल में उसको पूरा नहीं किया है।

वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे
हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे

महतारी वंदन योजना
विवाहित महिलाओं को
₹12,000/सालाना, अब तक कुल
₹655.57 करोड़ की सहायता

पिछले 2 वर्षों में
13लाख किसानों को **₹3,716 करोड़** लंबित धान बोनस का भुगतान

5 लाख 65 हजार भूमिहीन कृषि मजदूरों को
सालाना **₹10,000**, कुल **₹565 करोड़** की आर्थिक सहायता

तेंदू पत्ता पारिश्रमिक
₹4,000 से बढ़ाकर **₹5,500**

कृषक उन्नति योजना
24.75 लाख किसानों को
₹25,300 करोड़ इनपुट सब्सिडी

14 महीने
लाभार्थियों के खातों में
₹30,236 करोड़

कमल का बटन दबाएं • भाजपा को विजयी बनाएं

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.